स्वदेशी पत्रिका

वर्ष–20, अंक–4, चैत्र–वैशाख 2069, अप्रैल 2012

संपादक
विक्रम उपाध्याय

कार्यालय
धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022 से प्रकाशित
दूरभाष : 011–26184595
स्वदेशी जागरण समिति की ओर से ईश्वर दास महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

आवरण कथा–4

एक जनहित याचिका की सुनवाई के सिलसिले में सर्वोच्च न्यायालय ने देश में व्यापक भुखमरी और गरीबी के मद्देनजर आश्चर्य व्यक्त किया था कि सरकार गरीबी की एक नितांत अव्यवहारिक परिभाषा अपना रही है.

अ नु क्र म

आवरण कथा
विकास का असर या आंकड़ों की बाजीगरी
– डॉ. अश्विनी महाजन /4

कृषि
विज्ञान का लोकतांत्रिक चेहरा
– वंदना शिवा /6

अर्थव्यवस्था
ईरान के तेल का विकल्प
– डॉ. भरत झुनझुनवाला /8

अंतर्राष्ट्रीय
सीरिया के चलते बढ़ता वैश्विक तनाव
– अवधेश कुमार /11

विचार–विमर्श
उपलब्धियों से वंचित ब्रिक्स
– ब्रह्म चेलानी /14

विषमता
आर्थिक विषमता का चिंताजनक दौर
– जयंतीलाल भंडारी /17

सवाल–जवाब
मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ
– वेद प्रताप वैदिक /20

जनता का फैसला
सपा के अखिलेश यादव को जनाकांक्षाओं पर स्वयं को सिद्ध करना पड़ेगा
– डॉ. सूर्यप्रकाश अग्रवाल /21

पर्यावरण
गंगा के प्रति शून्य संवेदना
– राजेन्द्र सिंह /24

देख रही हो गंगा माई, अब हम हवा में उड़ रहे हैं
– रवीश कुमार /26

धरोहर : रामसेतु को बचाइये
– निरंकार सिंह /27

स्मरण
श्रद्धेय दत्तोपंत जी का अलौकिक सान्निध्य
– डॉ. रणजीत सिंह /30

पाठकनामा / 2, रपट / 34

पाठकनामा

आंकड़ों के जाल पर न जाकर, सरकार महंगाई को लगाए रोक

स्वदेशी पत्रिका अपने प्रत्येक अंक में देश की समस्याओं के बारे में कोई न कोई लेख अवश्य प्रकाशित करती रहती है जिससे पाठकों को देश की समस्याओं के बारे में पता चलता है। आज हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है – गरीबी। परंतु केन्द्र में बैठी सरकार, हमेशा गरीबों का मजाक ही उड़ाती रहती है। वर्ष 2009–10 में योजना आयोग की रिपोर्ट ने शहरी क्षेत्रों में 32 रूपंये प्रतिदिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 26 प्रतिदिन खर्च करने वाले को गरीब माना। वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो आज मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई जैसे शहरों में रहने वाला एक छोटा परिवार अर्थात् पति–पत्नी और दो बच्चे वाला परिवार जो 15 हजार रुपए प्रतिमाह कमाता हो और इन शहरों में किराये के मकानों में रहता हो, तो इनका गुजारा करना भी काफी मुश्किल होता है। फिर सरकार किस प्रकार गरीबी का आंकड़ा पेश करती है जिससे देश में रह रहे गरीबों का केवल मजाक ही उड़ाया जाता है। अभी हाल ही में एक जनहित याचिका की सुनवाई के सिलसिले में सर्वोच्च न्यायालय ने देश में व्यापक भुखमरी और गरीबी के मद्देनज़र आश्चर्य व्यक्त किया था कि सरकार गरीबी की एक नितांत अव्यवहारिक परिभाषा अपना रही है जिसके कारण जनता को गुमराह किया जा रहा है। आज वर्तमान सरकार, केवल गरीबी पर, केवल राजनीति कर रही है। उसे देश में रह रहे गरीबों की कोई चिंता नहीं है, उसे तो केवल गरीबों का मजाक उड़ना आता है जबकि आज गरीबों की आय महंगाई के चलते दिन–प्रति–दिन गिरती जा रही है। जहां सरकार को महंगाई पर लगाम लगानी चाहिए थी, वहीं वह दिन–प्रति–दिन गरीबी के आंकड़ों का विवरण देती रहती है। अगर यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब गरीबों को दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होगी।

– सुधीर रावत, फैबटेक ईवेन्ट सर्विस, अभय खण्ड–4, इंदिरापुरम, गाजियाबाद

शराब पर रोकथाम है जरूरी

आज देश में शराब पर पाबंदी जरूरी हो गई है। हर दिन अखबारों में अपराधों की खबर दिन–प्रति–दिन बढ़ती ही जा रही है। कभी चंद रुपयों की खातिर, तो कभी बदले की भावना से आदमी, आदमी को मार रहा है। इन हत्याओं और दुष्कर्मों की कहीं न कहीं सबसे बड़ी वजह नशाखोरी, चाहे वह शराब हो या अन्य तरह का जिसकी खुमारी व्यक्ति को आदमी, आदमी का अंतर भूलने पर मजबूर कर देता है। नशाखोरी से आदमी की सही गलत सोचने व समझने की क्षमता को बंद कर देता है और वह इतने बड़े अपराध कर बैठता है। एक सर्वे के अनुसार आज 75 से 80 प्रतिशत अपराध शराब पीने की वजह से होते हैं। देश की राजधानी दिल्ली का यह हाल है कि यहां का युवा वर्ग अपने पूरे दिनभर में पानी से ज्यादा शराब पीते हैं जिससे वे अपने आसपास का सामाजिक माहौल तक भी ताक पर रख देते हैं। वहीं दूसरी तरफ गुजरात में अपराध का ग्राफ सबसे कम हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां शराब पर रोकथाम है जिसके कारण वह प्रदेश सफलताओं की ऊंचाईयों पर आगे बढ़ रहा है। आज दिल्ली, उत्तराखण्ड, उत्तरप्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र सहित सभी राज्य सरकारों को भी शराब पर रोकथाम करना अनिवार्य है। सरकार अपना फायदा न देखकर जनता का फायदा देखें तभी सरकार इन अपराधों को कम कर सकती है।

– राकेश कुमार दास, अभयखण्ड–4, मीडियाअपार्टमेन्ट, गाजियाबाद।

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

"धर्मक्षेत्र" शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेल : swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 100 रुपए

आजीवन सदस्यता शुल्क: 1,000 रुपए

यदि शुल्क भेजने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

(ध्यानार्थ : कृपया अपना नाम व पता साफ अक्षरों में लिखें)

उन्होंने कहा

जिस दिन हमारे लोकसेवकों को यह अहसास हो जाएगा कि उन्हें इज्जत मांगने से नहीं, बल्कि कमाने से मिलेगी, उस दिन लोगों की सेवा का नजरिया ही बदल जाएगा।

– किरण बेदी

सेना प्रमुख को इस बात के लिए सलाम कि उन्होंने रिश्वत के मामले का खुलासा किया। कम से कम हमारे पास एक ऐसा प्रमुख है जो देश की सेवा करता है, नेताओं की नहीं।

– चेतन भगत

बजट की तरह नया कोयला घोटाला भी आज का मतदाता देखें कि देश में अर्थव्यवस्था किस तरह चौपट हो रही है।

– संतोष गंगवार

गरीबी निर्धारण के लिए तेंदुलकर समिति की आलोचना कर रहे सांसद शायद यह समझते हैं कि यह सचिन तेंदुलकर समिति है। वे सुरेश तेंदुलकर को जानते ही नहीं।

– जयराम रमेश

भारतीय संस्कृति में गाय का स्थान 'मां' से कम नहीं है। उससे प्राप्त होने वाला हरेक चीज काफी उपयोगी, लाभप्रद और अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अब गो–हत्या प्रतिबंध में कोताही बर्दाश्त नहीं ।

– सत्यानंद झा 'बादल'

विदेशी निवेश नहीं नीति की सही दिशा चाहिए

कुछ दिन पहले जब ब्रिक्स देशों के शासनाध्यक्ष स्थानीय करेंसी में आपसी व्यापार करने और ब्रिक्स विकास बैंक स्थापित करने के संबंध में निर्णय लेते हुए डॉलर, यूरो और अन्य अंतर्राष्ट्रीय करेंसियों को चुनौती देने का काम कर रहे थे, वहीं भारत सरकार निजी विमानन कंपनियों को राहत देने के नाम पर उनके 49 प्रतिशत शेयरों को विदेशी हाथों में बेचने की नीति को हरी झण्डी दिखाने की तैयारी कर रही थी। मल्टी ब्रांड खुदरा क्षेत्र में 51 प्रतिशत विदेशी निवेश न लागू करवा पाने की कुण्ठा में विमानन क्षेत्र में 49 प्रतिशत विदेशी निवेश की नीति को सरकार आर्थिक सुधार का नाम देने की कोशिश कर रही है।

देश विविध क्षेत्रों में विदेशी निवेश की नीति के नतीजे पहले से ही भुगत रहा है। सीमेण्ट क्षेत्र की अग्रणी कंपनी एसीसी कंपनी के विदेशियों द्वारा अधिग्रहण के चलते देश में सीमेण्ट की कीमतों में लगातार अनाप–शनाप वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के बार–बार चेताने के बावजूद विदेशियों द्वारा दवा कंपनियों के अधिग्रहण पर भारत सरकार द्वारा रोक न लगाए जाने के कारण देश में जेनेरिक दवाईयों की कीमतों में भारी वृद्धि के चलते देश का जन–स्वास्थ्य खतरे में पड़ चुका है। आज भारत की विमानन कंपनियां प्रबंधन अकुशलता से कम, महंगे ईंधन से ज्यादा प्रभावित हो रही हैं, सरकार द्वारा विदेशी निवेश की नीति ही एक मात्र समाधान मानी जा रही है। जरूरत इस बात की है कि विमान ईंधन पर टैक्स घटाकर उसे सस्ता करते हुए, विमानन कंपनियों की परिचालक लागत घटायी जाए। भारत की विमानन कंपनियों को विदेशी हाथों को सौंपा जाना देश के लोगों की सस्ती वायु यात्रा की आकांक्षाओं पर एक कुठाराघात होगा।

आज देश की अर्थव्यवस्था सरकार की प्रबंधन अकुशलता के कारण संकट में पड़ गई है। रूपए का अवमूल्यन और बढ़ती कीमतें किसी प्राकृतिक आपदा के कारण नहीं बल्कि सरकार की गलतियों का नतीजा है। सरकार निर्यात बढ़ने के नाम पर अपनी पीठ ठोंकने का काम कर रही है। लेकिन बढ़ते आयातों को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं हो रहा। बढ़ता व्यापार घाटा देश पर कर्ज बढ़ा रहा है। उधर सरकार द्वारा अपने खर्चों पर अंकुश न लगा पाने के कारण राजकोषीय घाटा बढ़ता जा रहा है। एक तरफ व्यापार घाटा और दूसरी ओर राजकोषीय घाटा, दोहरे घाटों के चलते आज अर्थव्यवस्था भारी मुश्किल में दिखाई दे रही है। उधर महंगाई से घबराकर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों को लगातार बढ़ाने की नीति देश में मांग पर दुष्प्रभाव डाल रही है। लगातार स्थिर औद्योगिक उत्पादन देश की चिंताओं को और बढ़ा रहा है।

समय की मांग है कि सरकार अर्थव्यवस्था के कुशल प्रबंधन हेतु प्रयास करे और यह समझे कि हर मुश्किल का हल विदेशी निवेश नहीं होता। हां विदेशी निवेश हमारी मुश्किलें बढ़ा जरूर सकता है।

विकास का असर या आंकड़ों की बाजीगरी

सरकार का यह भी कहना है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना इत्यादि के चलते भी गरीबी का प्रकोप घटा है। लेकिन यदि हम मामले की तह में जाते हैं तो पता चलता है कि वास्तव में सरकार द्वारा अभी भी गरीबी की वही गलत परिभाषा अपनाई जा रही है, जिसपर सर्वोच्च न्यायालय ने घोर आपत्ति दर्ज की थी। संसद में तो विरोधी पार्टियों ने इस कृत्य के लिए योजना आयोग के उपाध्यक्ष के त्याग-पत्र की मांग तक की है।

■ डॉ. अश्विनी महाजन

एक जनहित याचिका की सुनवाई के सिलसिले में सर्वोच्च न्यायालय ने देश में व्यापक भुखमरी और गरीबी के मद्देनजर आश्चर्य व्यक्त किया था कि सरकार गरीबी की एक नितांत अव्यवहारिक परिभाषा अपना रही है, जिसके अनुसार वर्ष 2004-05 में मात्र 37 प्रतिशत लोग ही गरीब थे।

यह तो गनीमत है कि प्रो. तेंदुलकर की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ दल ने गरीबी की एक बेहतर परिभाषा दी, अन्यथा भारत सरकार की पूर्व की परिभाषा के अनुसार तो 2004-05 में मात्र 27.5 प्रतिशत लोग ही गरीब रह गये थे। प्रो. तेंदुलकर की परिभाषा के अनुसार भी वर्ष 2004-05 में शहरी क्षेत्रों में 578.8 रूपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 446.7 रूपये से अधिक पाने वाले गरीबी की परिभाषा में नहीं आते।

जब सर्वोच्च न्यायालय ने योजना आयोग को इस संबंध में शपथ पत्र दाखिल करने को कहा तो भी योजना आयोग ने वर्ष 2009-10 के लिए गरीबी की परिधि में आने लायक आय को शहरी क्षेत्रों में 32 रूपये प्रतिदिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 26 प्रतिदिन ही माना।

ऐसे में जब देश में महंगाई के बोझ के तले दबी आम जनता का जीना दूभर हो गया है, सरकार के गरीबी के परिभाषा के संबंध में इस अड़ियल रूख के चलते सरकार की पहले ही बहुत किरकिरी हो चुकी थी। जबकि गरीबी की इस परिभाषा के मद्देनजर देश में एक बहस शुरू हो चुकी है कि क्या सरकार गरीबों और गरीबी निवारण के प्रति संवेदनशील है भी कि नहीं, योजना आयोग द्वारा हाल ही में जारी गरीबी के आकड़ों ने तो जैसे पुराने जख्म पर फिर से नमक डाल दिया है।

सोमवार 21 मार्च 2012 को जारी आकड़ों के अनुसार भारत में गरीबों की संख्या 2004-05 में जनसंख्या के 37 प्रतिशत से घटते हुए अब लगभग 30 प्रतिशत ही रह गई है। सरकार द्वारा इन आंकड़ों को औचित्यपूर्ण ठहराया जा रहा है।

योजना आयोग का कहना है कि देश में तेजी से हुई आर्थिक प्रगति और सरकार द्वारा चलाये जा रहे महात्मा गांधी नरेगा कार्यक्रम, जिसमें हर वर्ष 100 रूपये प्रतिदिन की दर से न्यूनतम 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है, के चलते यह गरीबी घटी है। सरकार का यह भी कहना है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना इत्यादि के चलते भी गरीबी का प्रकोप घटा है।

लेकिन यदि हम मामले की तह में जाते हैं तो पता चलता है कि वास्तव में

सरकार द्वारा अभी भी गरीबी की वही गलत परिभाषा अपनाई जा रही है, जिसपर सर्वोच्च न्यायालय ने घोर आपत्ति दर्ज की थी। संसद में तो विरोधी पार्टियों ने इस कृत्य के लिए योजना आयोग के उपाध्यक्ष के त्याग–पत्र की मांग तक की है।

आलोचकों का कहना है कि योजना आयोग ने अत्यंत गैर जिम्मेदारीपूर्वक एक गरीबी की रेखा की एक नई परिभाषा गढ़ दी है। नई परिभाषा के अनुसार एक व्यक्ति जो शहरी क्षेत्रों में 28.7 रूपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 22.5 रूपये दैनिक आमदनी प्राप्त करता है, वो गरीबी की रेखा से ऊपर माना जायेगा।

गौरतलब है कि योजना आयोग स्वयं सर्वोच्च न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल कर यह कह चुका है कि शहरी क्षेत्रों में 32 रूपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 28 रूपये से कम पाने वाला गरीबी की रेखा से नीचे माना जायेगा। ऐसे में 2004–05 से 2009–10 के बीच जबकि कीमतें ही 60 प्रतिशत बढ़ गई तो गरीबी की रेखा कैसे नीचे पहुंच गई, यह समझ के परे है।

जाहिर है कि परिभाषा बदलते हुए आकड़ों की कारीगरी से तो गरीबी को किसी भी स्तर पर लाया जा सकता है, उसमें सरकार द्वारा कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। गरीबी की रेखा को बदलते हुए अचानक गरीबी को घटाने की कवायद कोई नई बात नही है। इससे पहले भी सर्वप्रथम सरकार द्वारा वर्ष 1993–94 में गरीबी की परिभाषा को बदलते हुए गरीबी के आंकड़ों को कम दर्शाने का प्रयास हुआ था और यह अभी तक चल रहा है।

सरकार द्वारा यह कहा जा रहा है कि वर्ष 2004–05 से 2009–10 के बीच 8.9 प्रतिशत औसत आर्थिक संवृद्धि के फलस्वरूप गरीबों की प्रतिशत की संख्या घटना स्वाभाविक ही है। और इस कारण वर्ष 2004–05 में जहां गरीबों की संख्या 40.7 करोड़ थी, वह घटकर 2009–10 में 35.5 करोड़ ही रह गई। इसका कारण यह बताया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी नरेगा सरीखी योजनाओं के कारण ज्यादा तेजी से घटी है।

लेकिन जहां तक सरकार का यह तर्क है कि गरीबी का घटना नरेगा के कारण हुआ है, शायद सही नहीं है। सरकार का कहना है कि चूंकि नरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारंटी देता है इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 4.8 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गये। लेकिन नरेगा और गरीबी का संबंध धरातल पर दिखाई नहीं देता और न ही ऐसा दिखाई देता है कि आर्थिक संवृद्धि गरीबी को घटा रही है।

उदाहरण के लिए बिहार द्वारा 2004–05 से 2009–10 के कालखंड में 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से आर्थिक संवृद्धि रिकार्ड की गई, लेकिन वहां गरीबी नहीं घट पाई। सरकारी तंत्र का कहना है कि शायद नरेगा में बिहार का प्रदर्शन अच्छा नहीं होने के कारण ऐसा हुआ।

जहां मध्यप्रदेश में नरेगा को गरीबी घटने का कारण बताने का प्रयास हो रहा है तो महाराष्ट्र और उड़ीसा में आर्थिक संवृद्धि को गरीबी घटाने के लिये जिम्मेवार माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश और असम में नीची आर्थिक संवृद्धि और नरेगा के धन का कम उपयोग दोनों गरीबी न घटने के लिये जिम्मेवार बताये जा रहे हैं।

अर्थशास्त्रियों का एक बड़ा वर्ग गरीबी घटने के आंकड़ों को पूरी तरह से मानने के लिये तैयार नहीं है। कुछ अर्थशास्त्री हालांकि गरीबी घटने की बात आंशिक रूप से तो मानते हैं, तो भी उनका कहना है कि गरीबी में इतनी कमी नहीं मानी जा सकती। उनका मानना है कि गरीबी की रेखा को परिभाषित करने में गलती हुई है।

योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि गरीबी की रेखा में कुछ गलती हुई है, क्योंकि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के आंकड़ों और राष्ट्रीय लेखा के आंकड़ों के बीच में गंभीर अंतर है। हालांकि उन्होंने इसे सांख्यिकी संबंधी समस्या बनाकर टाल दिया है। लेकिन आलोचकों का मानना है कि यह गड़बड़ झाला वास्तव में सरकार की ईमानदारी पर संदेह खड़ा करता है, क्योंकि इसके द्वारा गरीबों की संख्या को कम आंकने का प्रयास किया गया है।

लेकिन एक विषय जिस पर कोई चर्चा नहीं हो रही, वह है, देश में बढ़ती असमानताएं। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि देश में औसत आमदनी बढ़ी है। आज देश की प्रति व्यक्ति आय (चालू कीमतों पर) लगभग 53,000 रूपये प्रति वर्ष पहुंच चुकी है। लेकिन यह गरीबी घटाने के लिये पर्याप्त उपाय नहीं है।

ऐसा इसलिये है कि गरीब आदमी की आय में उतनी वृद्धि नहीं हो पा रही क्योंकि देश में आय की असमानताओं में निरंतर वृद्धि हो रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भी 2004–05 से 2009–10 के बीच 5 वर्षों में आय की असमानताएं तेजी से बढ़ी हैं। आय की असमनताओं का सूचक गिनी चरांक 0.35 से बढ़कर 0.37 हो गया है। असमानताओं में यह वृद्धि सभी प्रांतों में दिखाई देती है। ❑

विज्ञान का लोकतांत्रिक चेहरा

प्रधानमंत्री 'दोहरी मार' की चर्चा तो करते हैं, लेकिन वह इसे एक 'अवसर' के रूप में भी देखते हैं। वह अब तक ढाई लाख किसानों की आत्महत्या, देश में गहराते कृषि और खाद्य संकट और बच्चों की कुल संख्या की आधी फीसदी आबादी के कुपोषित होने जैसे मसलों का हल तलाशने में विफल रहे हैं। उन्हें समझना होगा कि जीएमओ इन समस्याओं का समाधान नहीं है। जीएमओ बीजों के एकाधिकार पर आधारित पूंजीगत गैर–टिकाऊ कृषि से जुड़े कर्ज संकट को और बढ़ा रहा है।

■ वंदना शिवा

हाल ही में साइंस पत्रिका को दिए एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बताया था कि देश में विज्ञान के विकास के लिए दो तकनीकों पर ध्यान देना जरूरी है – पहला कृषि में जीई (जेनेटिक इंजीनियरिंग) बीज और फसल का उपयोग तथा दूसरा परमाणु ऊर्जा।

दुर्भाग्य से, हमारी अर्थव्यवस्था की उन्नति के लिए ये दोनों ही तकनीकें खतरनाक हैं। तब प्रधानमंत्री ने गैरसरकारी संगठनों पर भी उंगली उठाते हुए कहा था कि ये संस्थाएं विदेशी हाथों में खेल रही हैं और 'विकास कार्यों' में बाधा उत्पन्न कर रही हैं।

प्रधानमंत्री का यह बयान बताता है कि वह न सिर्फ विज्ञान से दूर हैं, बल्कि आम लोगों से भी दूर हैं, लोकतंत्र में जिसके प्रतिनिधित्व का वह दावा करते हैं।

बल्कि ऐसी खतरनाक तकनीकों के इस्तेमाल को रोकने के लिए संघर्ष कर रहे एनजीओ में 'विदेशी पूंजी' लगने की बात कहकर वह देश को गुमराह करने का काम ही रहे हैं। जिम्मेदार और लोकतांत्रिक विज्ञान के विकास की दिशा में प्रधानमंत्री को डॉ पुष्प भार्गव (देश में आणविक जीव विज्ञान के जनक और जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि), डॉ. ए. गोपाल कृष्णन (परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के पूर्व चेयरमैन) जैसे विशेषज्ञों की राय सुननी चाहिए, न कि 'विदेशी हाथ' का हौवा खड़ा कर उन सामाजिक आंदोलनों अथवा जन हितैषी समूहों पर चोट करनी चाहिए, जो किसी भी लोकतंत्र में खून की तरह हैं।

दरअसल, देश में जीएमओ (जेनेटिकली मोडिफाइड ऑर्गेनिज्म) और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को प्रमुखता से आगे बढ़ाने के लिए ही उन आंदोलनों को कुचला जा रहा है, जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग और

पहला कृषि में जीई (जेनेटिक इंजीनियरिंग) बीज और फसल का उपयोग तथा दूसरा परमाणु ऊर्जा। दुर्भाग्य से, हमारी अर्थव्यवस्था की उन्नति के लिए ये दोनों ही तकनीकें खतरनाक हैं। तब प्रधानमंत्री ने गैरसरकारी संगठनों पर भी उंगली उठाते हुए कहा था कि ये संस्थाएं विदेशी हाथों में खेल रही हैं और 'विकास कार्यों' में बाधा उत्पन्न कर रही हैं।

परमाणु ऊर्जा से जुड़ी सुरक्षा संबंधी चिंताओं को उठाया जाता है। निर्विवाद है कि ये हमले विदेशी कॉरपोरेट घरानों की शह पर हो रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री भी इन घरानों के दबाव में आकर देश की खाद्य और ऊर्जा संप्रभुता से समझौता करने को तैयार हो गए हैं।

उन्होंने अमेरिका के साथ परमाणु समझौता किया, जिसका संसद से अनुमोदन 'वोट के बदले नोट' कांड के बाद ही हो सका। इसी तरह हमारी सरकार ने अमेरिका के साथ खेती से जुड़ा करार किया, जिसमें हमारी खाद्य और कृषि व्यवस्थाओं को मोनसेंटो, कारगिल और वॉलमार्ट जैसी विदेशी कॉरपोरेट के हाथों बंधक हो जाना है।

बहरहाल, संसद ने खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को लागू करने की कोशिशें विफल कर दीं। आम लोगों ने भी विधानसभा चुनावों में बता दिया कि वे केंद्र सरकार की उन नीतियों के खिलाफ हैं, जो वैश्विक निगमों के हितों का पोषण करती हैं, क्योंकि ये नीतियां आजीविका खत्म कर रही हैं और उनके लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचल रही हैं।

हमने पहले ही देखा कि मोनसेंटो के आने के बाद किस तरह कपास के बीज पर अपनी संप्रभुता समाप्त हुई। आज कपास के हमारे बीजों का 95 फीसदी मोनसेंटो खरीद लेती है। नतीजतन देश में कपास बीजों की लागत 8,000 फीसदी बढ़ी, कपास की फसल के खराब होने की आशंका बढ़ी, कीटाणुनाशकों का प्रयोग बढ़ा, किसानों पर कर्ज बढ़ा और किसान–आत्महत्या महामारी के रूप में उभरी।

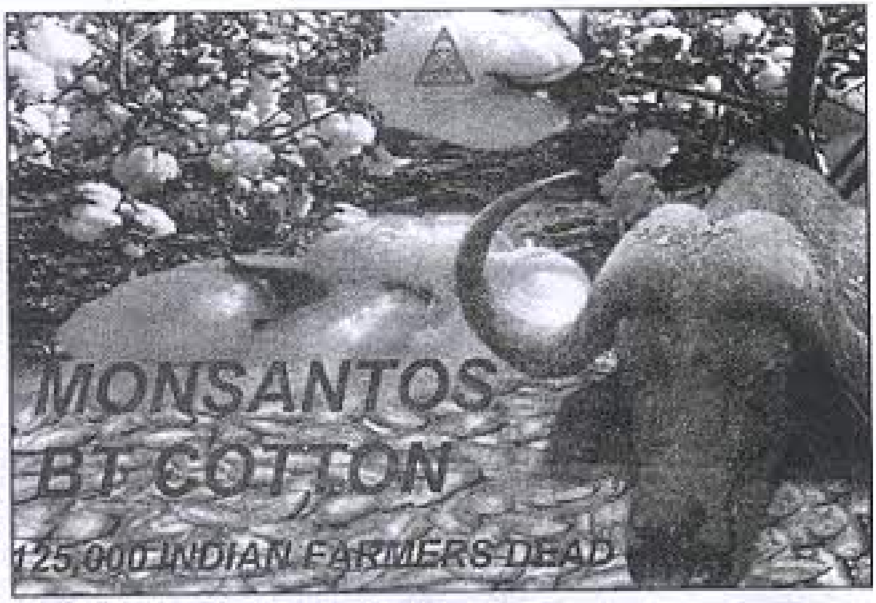

प्रधानमंत्री इस 'दोहरी मार' की चर्चा तो करते हैं, लेकिन वह इसे एक 'अवसर' के रूप में भी देखते हैं। वह अब तक ढाई लाख किसानों की आत्महत्या, देश में गहराते कृषि और खाद्य संकट और बच्चों की कुल संख्या की आधी फीसदी आबादी के कुपोषित होने जैसे मसलों का हल तलाशने में विफल रहे हैं। उन्हें समझना होगा कि जीएमओ इन समस्याओं का समाधान नहीं है। जीएमओ बीजों के एकाधिकार पर आधारित पूंजीगत गैर–टिकाऊ कृषि से जुड़े कर्ज संकट को और बढ़ा रहा है।

इससे स्वस्थ और पोषक खाद्य पदार्थों से भरपूर हमारा खाद्य तंत्र नष्ट हो रहा है। असल में, किसानों की आत्महत्या और बाल कुपोषण जैसी समस्याओं के हल कृषि पारिस्थितिकी के विज्ञान और पारिस्थितिकी अनुकूलता के विकास में छिपे हैं। रासायनिक खादों का इस्तेमाल कम होने से स्वाभाविक रूप से उत्पादन लागत कम होगी और उसमें पोषक तत्व भी होंगे।

लिहाजा यह कहना गलत नहीं कि समाज और पारिस्थितिकी की कीमत पर एक विफल तकनीक को 'विज्ञान' के नाम पर लागू किया जा रहा है, जो विरोधी–विज्ञान और अलोकतांत्रिक है। यह इसलिए भी विरोधी–विज्ञान है, क्योंकि वास्तविक विज्ञान कृषि–पारिस्थितिकी और जीनों में आनुवांशिक बदलाव के नए नियमों पर आधारित होता है, न कि आनुवांशिक नियतिवाद के अप्रचलित विचारों पर।

इसी तरह ऊर्जा के क्षेत्र में नया विज्ञान अक्षय ऊर्जा है, न कि आणविक ऊर्जा। मगर क्या वैश्विक कॉरपोरेट घरानों से प्रभावित प्रधानमंत्री देश की बीज संप्रभुता, खाद्य संप्रभुता, ऊर्जा संप्रभुता और स्वास्थ्य तथा पोषण संप्रभुता को नष्ट करने वाली नीतियों को रोकेंगे? इस परिदृश्य में देखें, तो साइंस में दिया गया प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लोकतंत्र और लोक अधिकारों पर हो रहे हमले का ही एक हिस्सा है, जिसमें खाद्य और ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक कॉरपोरेट घरानों की भूमिका को अलोकतांत्रिक तरीके से स्थापित किया जाता है। ❑

ईरान के तेल का विकल्प

ईरान से आयात जारी रखने पर अमरीका हमसे नाराज हो जायेगा और उससे हमें मिलने वाली पूंजी तथा तकनीक बाधित होगी। मेरी दृष्टि से यह प्रभाव नगण्य होगा। भारत पूंजी का निर्यातक बन चुका है। हमारे उद्यमियों द्वारा विदेशों में निवेश अधिक किया जा रहा है। फिर भी जो पूंजी आ रही है उसमें कटौती होने की सम्भावना है।

■ डॉ. भरत झुनझुनवाला

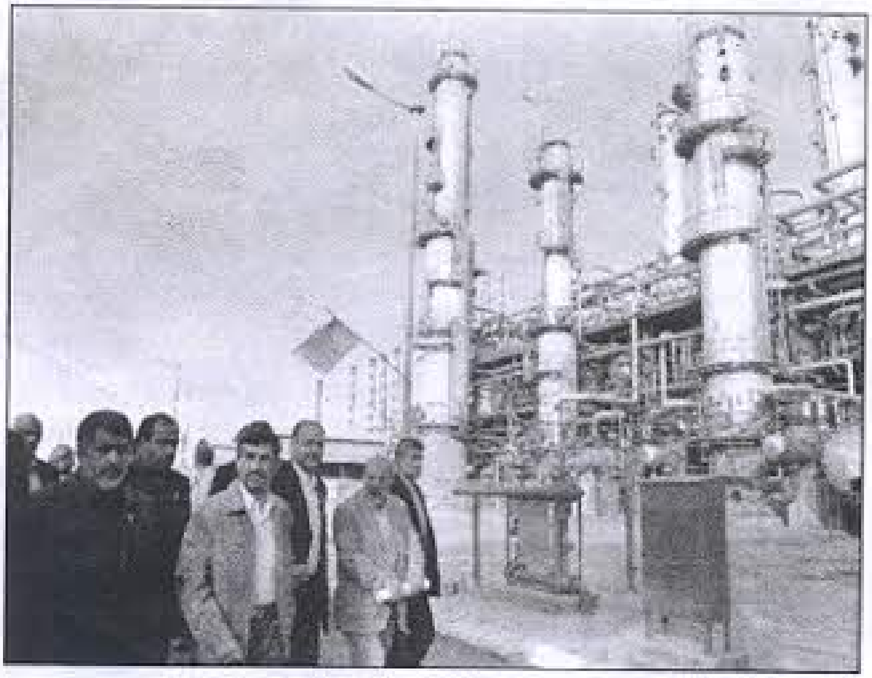

अमरीका की शिकायत ईरान के परमाणु अस्त्र कार्यक्रम को लेकर है। ईरान ने परमाणु अप्रसार ट्रीटी पर दस्तखत कर रखे हैं। ईरान का कहना है कि वह कामर्शियल उर्जा के उत्पादन के लिये परमाणु रियेक्टर लगा रहा है। अमरीका का मानना है कि यह ऊपरी आवरण है।

वास्तव में ईरान परमाणु अस्त्र बनाने का प्रयास कर रहा है। दोनों तथ्य के बीच सत्य का पता लगाना कठिन है।

अमरीका की स्ट्रेटजी ईरान के मध्य वर्ग को भड़काने की दिखती है। ईरान की घेरेबन्दी करके अमरीका उस देश को डुबोना नहीं चाहता है। पूर्व में ऐसा उत्तरी कोरिया के साथ किया गया था। कोरिया को फर्टिलाइजर और तेल की उपलब्धि बाधित कर दी गयी थी। फलस्वरूप वहां की खेती चौपट हो गयी। भीषण अकाल पड़ा और अनेक लोग काल कलवित हो गये। अन्ततः पश्चिमी देशों को खाद्य

उर्जा संकट गहराने के संकेत मिल रहे हैं। राष्ट्रपति ओबामा ने तेल के बढ़ते वैश्विक दामों को भारत और चीन द्वारा तेल की बढ़ती खपत के कारण बताया है। इंडोनेशिया एवं आस्ट्रेलिया जैसे निर्यातक देशों ने कोयले के दाम में वृद्धि की है। अपनी उर्जा की जरूरतों के लिये हम आयातों पर निर्भर हैं।

उर्जा के चार प्रमुख स्रोत हैं कोयला, यूरेनियम, तेल तथा जलविद्युत। हमारे कोयले के भंडार लगभग 200 वर्षों के लिये पर्याप्त हैं। परन्तु हमारे कोयले की क्वालिटी घटिया है। यदि हम कोयले का अति दोहन करेंगे तो 50 से 100 वर्षों में ही यह समाप्त हो जायेगा और हम ज्यादा कठिन परिस्थिति में अपने को पायेंगे।

यूरेनियम तथा तेल हमें लगभग पूर्णतया आयात करना पड़ता है। जलविद्युत के उत्पादन में हमारा पर्यावरण और संस्कृति नष्ट होती है। इस पृष्ठभूमि में हमें अमरीका द्वारा दबाव डाला जा रहा है कि ईरान से तेल का आयात कम करें।

अमरीका की स्ट्रेटजी ईरान के मध्य वर्ग को भड़काने की दिखती है। ईरान की घेरेबन्दी करके अमरीका उस देश को डुबोना नहीं चाहता है। पूर्व में ऐसा उत्तरी कोरिया के साथ किया गया था। कोरिया को फर्टिलाइजर और तेल की उपलब्धि बाधित कर दी गयी थी। फलस्वरूप वहां की खेती चौपट हो गयी।

सामग्री पहुंचानी पड़ी। अमरीका सैन्य कार्यवाही भी नहीं करना चाहता है क्योंकि इससे मुस्लिम वर्ल्ड में गलत मैसेज जायेगा।

ईराक और अफगानिस्तान की तुलना में ईरान बड़ा देश है जिसे फतह करना कठिन होगा। अतः अमरीका की स्ट्रेटजी है कि ईरान के मध्यम वर्ग पर दबाव बनाओ।

ईरान मध्य वर्गीय खपत के लिये इलेक्ट्रानिक उपकरण जैसे माल का आयात करता है। इसका भुगतान तेल के निर्यात से मिली रकम से किया जाता है। तेल का निर्यात बाधित होने पर ईरान द्वारा मध्य वर्ग के खपत की पूर्ति करना कठिन हो जायेगा। संभव है कि तब यह वर्ग अपने शासकों के विरूद्ध खड़ा हो जाये।

अमरीका द्वारा उन सभी देशों पर दबाव बनाया जा रहा है जो ईरान से तेल का आयात कर रहे हैं। वर्तमान में भारत, चीन तथा जापान द्वारा ईरान का 45 प्रतिशत तेल खरीदा जा रहा है। अमरीका और जापान के बीच समझौता होने का समाचार है जिसके अंतर्गत जापान द्वारा ईरान से आयातित तेल में 11 प्रतिशत की कटौती की जायेगी।

खबर है कि भारत सरकार ने भी तेल कम्पनियों को 10 प्रतिशत कटौती करने को कहा है। ईरान के पास तेल का भारी स्टाक एकत्रित हो गया है चूंकि यूरोप को निर्यात बन्द कर दिया गया है। लेकिन यह कहना कठिन है कि यह दबाव ईरानी सरकार के विरूद्ध भड़केगा या अमरीका के विरूद्ध। पूर्व में ऐसी ही परिस्थिति में ईरान के लोगों ने अमरीकी दूतावास पर कब्जा कर लिया था।

ऐसे में हमें तय करना है कि हम ईरान से तेल के आयात में कटौती करें या नहीं? पहला बिन्दु उर्जा सुरक्षा का है। हमारी उर्जा की बढ़ती खपत को देखते हुये ईरान से आयात में कटौती करना कष्टप्रद होगा। हमें दूसरे देशों से महंगा तेल खरीदना होगा जिससे महंगाई बढ़ेगी।

दूसरा बिन्दु देश के मुसलमानों की भावनाओं का है। इनका झुकाव निःसंदेह ईरान की ओर है। भारत सरकार के द्वारा ईरान के विरूद्ध कदम उठाने से हमारे मुसलमान भाई क्षुब्ध होंगे। तीसरा बिन्दु पाकिस्तान–अफगानिस्तान–ईरान के समूह का है। पाकिस्तान को घेरने में ईरान हमारी मदद कर सकता है। ईरान के हमारे विमुख होने पर अफगानिस्तान में अपना प्रभाव बनाये रखना भी कठिन हो जायेगा।

चौथा बिन्दु तेल के पेमेन्ट का है। ईरान ने निर्यातित तेल की रकम का 45 प्रतिशत रुपयों में लेना स्वीकार किया है। सामान्यतया हम आयातित तेल का पेमेन्ट डालर अथवा दूसरी परिवर्तनीय मुद्रा में करते हैं। अर्थात् बासमती चावल, साफ्टवेयर तथा मसालों के निर्यात से हम विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं। इस मुद्रा को तेल के पेमेन्ट में ईरान को देते हैं। निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित करने की जिम्मेवारी हमारी है। ईरान द्वारा रुपये में पेमेन्ट लेने में हम इस जिम्मेवारी से मुक्त हो जाते हैं।

तेल के लिये मिले रुपयों से ईरान कपड़े, अनाज अथवा अन्य दूसरा माल भारत से खरीद सकता है। यह सौदा भारत के लिये लाभप्रद है।

पांचवां बिन्दु विश्व अर्थव्यवस्था का है। पश्चिमी विशेषज्ञों का आकलन है कि ईरान से तेल की सप्लाई बाधित होने पर विश्व अर्थव्यवस्था मंदी में जा सकती है। तेल के वैश्विक दाम बढ़ेंगे। विश्व अर्थव्यवस्था मंद पड़ेगी और हमारे निर्यातों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूँ। तेल के मूल्य बढ़ने से विश्व अर्थव्यवस्था पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा।

जितना घाटा जर्मनी एवं फ्रांस जैसे आयात करने वाले देशों को होगा

उतना ही मुनाफा रूस, सऊदी अरब एवं नाइजीरिया जैसे निर्यातक देशों को होगा। विश्व अर्थव्यवस्था का ग्रोथ सेन्टर आयात करने वाले देशों से हटकर निर्यात करने वाले देशों की ओर बढ़ेगा।

सब्जी महंगी होने से किसान को लाभ और मध्य वर्ग को हानि होती है परन्तु अर्थव्यवस्था पर विशेष असर नहीं पड़ता है। इसी प्रकार तेल के दाम से देश विशेष को लाभ एवं हानि होगी परन्तु विश्व अर्थव्यवस्था पर न्यून प्रभाव पड़ेगा। हमारे जो निर्यात जर्मनी और फ्रांस को जा रहे हैं उनकी दिशा ईरान, नाइजीरिया, रूस तथा वेनेजुएला की ओर मुड़ेगी। परन्तु हमें भी दूसरे देशों से महंगा तेल खरीदना पड़ेगा जिससे हानि होगी।

छठा बिन्दु अमरीका की नाराजगी का है। ईरान से आयात जारी रखने पर अमरीका हमसे नाराज हो जायेगा

हमें अपनी उर्जा की खपत घटानी ही होगी। ऐसी जीवन शैली अपनानी होगी जो हमारे प्राकृतिक संसाधनों के अनुरूप हो। अपनी भूमि पर उत्पन्न होने वाली उर्जा से अधिक खपत करने का कारण हम आयातों पर आश्रित हो जायेंगे और हमारी उर्जा सुरक्षा संकट में पड़ जायेगी. . .

और उससे हमें मिलने वाली पूंजी तथा तकनीक बाधित होगी। मेरी दृष्टि से यह प्रभाव नगण्य होगा। भारत पूंजी का निर्यातक बन चुका है। हमारे उद्यमियों द्वारा विदेशों में निवेश अधिक किया जा रहा है। फिर भी जो पूंजी आ रही है उसमें कटौती होने की सम्भावना है।

वर्तमान में आधुनिक तकनीकों मे अमरीका अग्रणी है। अमरीका की यह अगुआई कुछ धीमी पड़ रही है परन्तु अभी अमरीका बहुत आगे है। ईरान से तेल का आयात जारी रखने से आधुनिक तकनीकों का मिलना कठिन हो जायेगा।

अन्ततः हमें अपनी उर्जा की खपत घटानी ही होगी। ऐसी जीवन शैली अपनानी होगी जो हमारे प्राकृतिक संसाधनों के अनुरूप हो। अपनी भूमि पर उत्पन्न होने वाली उर्जा से अधिक खपत करने का कारण हम आयातों पर आश्रित हो जायेंगे और हमारी उर्जा सुरक्षा संकट में पड़ जायेगी। अतः हमें उर्जा की सप्लाई को दो समानान्तर चैनलों में करना चाहिये जैसे एलपीजी के डोमेस्टिक और कामर्शियल सिलेंडर अलग–अलग होते हैं। मूलभूत जरूरतों जैसे रेलवे आदि के लिये उर्जा को पहले उपलब्ध कराना चाहिये। एयरकंडीशंड माल के स्थान पर अस्पताल आदि को प्राथमिकता देते हुये उर्जा की अनुत्पादक खपत को कम करना ही उर्जा संकट से उबरने का अंतिम उपाय है। ❑

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका साम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

हमारा पता है :–

संपादक

स्वदेशी पत्रिका

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

सीरिया के चलते बढ़ता वैश्विक तनाव

गहराई से देखें तो सीरिया के संकट ने शीतयुद्ध की दो पूर्व शक्तियों के बीच नई तनावपूर्ण प्रतिद्वंद्विता तथा शिया–सुन्नी समुदायों के नेतृत्वकारी शक्तियों के बीच क्षेत्रीय प्रभाव के लिए तीखे युद्ध को रेखांकित किया है जनमत संग्रह को विद्रोहियों के नकारने तथा उन्हें पश्चिमी देशों के समर्थन के कारण हिंसा अभी रुकने वाली नहीं। प्रतिबंधों के कारण सीरिया की समस्याएं बढ़ रहीं हैं पर न असद आसानी से इस्तीफा देने वाले हैं और न पश्चिम इस संविधान को मान्यता देने वाला है।

■ अवधेश कुमार

जिन दो खाड़ी देशों के कारण इस समय पूरी दुनिया संकट के साए में दिख रही है, वे हैं ईरान और सीरिया। यह आश्चर्य का ही विषय है कि भारत में जितनी चर्चा ईरान की हो रही है उतनी सीरिया की नहीं। आखिर सीरिया में प्रतिदिन दर्जनों लोगों के मारे जाने की सूचना आ रही है तथा क्षेत्रीय देशों एवं दुनिया के प्रमुख देशों के बीच भी उसके कारण तनाव गहरा रहा है।

हालांकि मरने वालों की संख्या की पुष्टि कठिन है पर विरोधियों के अनुसार एक वर्ष के संघर्ष में कम से कम हजार लोग मारे गए हैं। इतने लोग न ईराक में प्रतिवर्ष मारे जा रहे हैं, न अफगानिस्तान में। जिस तेल संकट का हम सामना कर रहे हैं, उसका एक प्रमुख कारण सीरिया ही है। ईरान का योगदान तो उसमें अब होगा।

अमेरिका सहित पूरा यूरोपीय संघ सीरिया के राष्ट्रपति बशर अहमद को पदच्युत कर उन पर मुकदमा चलाने की इच्छा रखता है। इसके विपरीत असद के साथ खाड़ी में ईरान खड़ा है तो बाहर रूस और चीन। प्रश्न है कि सीरिया का होगा क्या? क्या वह आंतरिक हिंसा से ग्रस्त एक अस्थिर और अराजक देश में तब्दील होकर दुनिया के लिए समस्या बनेगा या शांत होगा? क्या वह पश्चिमी देशों तथा रूस, चीन के बीच नई प्रतिद्वंद्विता या टकराव का कारण बनेगा? पश्चिमी देशों की मांग के विपरीत असद ने नए संविधान की रचना कराई तथा उस पर जनमत संग्रह कराने के बाद सरकार ने घोषणा की है कि जनता ने उस प्रस्तावित संविधान का समर्थन किया है।

आखिर सीरिया में प्रतिदिन दर्जनों लोगों के मारे जाने की सूचना आ रही है तथा क्षेत्रीय देशों एवं दुनिया के प्रमुख देशों के बीच भी उसके कारण तनाव गहरा रहा है। हालांकि मरने वालों की संख्या की पुष्टि कठिन है पर विरोधियों के अनुसार एक वर्ष के संघर्ष में कम से कम हजार लोग मारे गए हैं। इतने लोग न ईराक में प्रतिवर्ष मारे जा रहे हैं, न अफगानिस्तान में। जिस तेल संकट का हम सामना कर रहे हैं, उसका एक प्रमुख कारण सीरिया ही है।

साफ है कि असद इन मांगों के सामने झुकने वाले नहीं, जिसने भी

चीन ने कहा है, 'पश्चिमी देशों ने सीरिया की समस्या तथा लोगों की कठिनाइयों का अंत कैसे हो, इस पर विचार ही नहीं किया। वे सीरिया में किसी सुधार की पूर्व शर्त बशार की विदाई बना चुके हैं, जो गलत है। जो कुछ पश्चिम चाहता है, वह लोकतंत्र नहीं है, बल्कि वे सीरिया से ईरान के प्रभाव का अंत करने के लिए बशर का तख्ता पलटना चाहते हैं। चीन, रूस के साथ मिलकर सीरिया के जनमत संग्रह का समर्थन करेगा।'

टेलीविजन चौनलों पर सीरिया के राष्ट्रपति बशर अहमद को जनमत संग्रह में मतदान करते देखा होगा, वे उनके चेहरे के हाव–भाव से अवश्य ही आश्चर्यचकित हुए होंगे। जिसके खिलाफ पूरी दुनिया में आवाज उठ रही है, अमेरिका और यूरोप के साथ जिस पर अरब लीग तक ने प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिस पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में नरसंहार का मामला चलाने की तैयारी हो रही है, उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं। अपनी पत्नी के साथ मुस्कराते हुए मतदान करते असद को देखकर लगा ही नहीं कि वे किसी दबाव या तनाव में हैं।

सरकार ने दावा कर दिया है कि 89 प्रतिशत मतदाताओं ने संविधान के दस्तावेज को समर्थन दिया है। हालांकि विरोधी जनमत संग्रह के दिन व्यापक नरसंहार के आरोप लगा रहे हैं। विरोधियों के अनुसार जिस जनमत संग्रह के दौरान कम से कम 125 लोग अलग–अलग स्थानों पर सरकारी हिंसा में मारे गए, उसे मान्यता कैसे दी जा सकती है? सीरिया का होम्स शहर सेना एवं विरोधियों के बीच टकराव का केंद्र बना हुआ है लेकिन सरकार का कहना है कि कुल मतदाताओं में से 57 प्रतिशत ने मताधिकार का प्रयोग किया। आंतरिक मामलों के मंत्री मेजर जनरल इब्राहिम शार के अनुसार अगर सशस्त्र आतंकवादियों ने कुछ क्षेत्रों में दहशत पैदा नहीं की होती तो मतदान का प्रतिशत ज्यादा होता। वैसे इस संविधान के लागू होने के साथ करीब 40 सालों से सीरिया पर हुकूमत कर रहे असद के परिवार एवं उनकी बाथ पार्टी का एकाधिकार समाप्त होगा एवं बहुदलीय प्रणाली का आविर्भाव होगा।

हालांकि संविधान का यह प्रारूप पश्चिमी देशों की कल्पना के अनुरूप नहीं है और वे जिस शासक को नरसंहार, नागरिकों के मानवाधिकारों का हरणकर्ता मान चुके हों उसके किसी कदम का समर्थन नहीं कर सकते। लेकिन विश्व क्षितिज पर असद के समर्थक रूस, चीन और ईरान ने इस जनमत संग्रह का समर्थन कर दिया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने सीरिया में जनमत संग्रह के बाद पश्चिमी देशों के खिलाफ तीखा बयान दिया एवं संभावित हमले के विरुद्ध चेतावनी दी।

पुतिन ने एक समाचार पत्र में अपनी लिखित प्रतिक्रिया में जो कहा, उसके एक अंश पर नजर दौड़ाइए, 'किसी को भी सीरिया में लीबिया का दृश्य पैदा करने नहीं दिया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय समुदाय सीरिया के अंदर मेल–मिलाप का लक्ष्य पाने के लिए काम करे। मैं अपने पश्चिमी साथियों को पूर्व में अपनाए गए उन साधारण उपायों के विरुद्ध चेतावनी देना चाहूंगा जिसमें कहा गया कि अगर सुरक्षा परिषद ने कार्रवाई की अनुमति दी तो ठीक नहीं तो हम कुछ देशों का

गठजोड़ बनाएंगे एवं हमला करेंगे।'

इसी तरह, चीन ने कहा है, 'पश्चिमी देशों ने सीरिया की समस्या तथा लोगों की कठिनाइयों का अंत कैसे हो, इस पर विचार ही नहीं किया। वे सीरिया में किसी सुधार की पूर्व शर्त बशार की विदाई बना चुके हैं, जो गलत है। जो कुछ पश्चिम चाहता है, वह लोकतंत्र नहीं है, बल्कि वे सीरिया से ईरान के प्रभाव का अंत करने के लिए बशर का तख्ता पलटना चाहते हैं। चीन, रूस के साथ मिलकर सीरिया के जनमत संग्रह का समर्थन करेगा।'

इस तरह के रवैये के व्यावहारिक निहितार्थ समझना कठिन हैं। किसी कार्रवाई में रूस या चीन बशर के पक्ष में सैनिक शायद ही भेजेंगे। बयानबाजी एक बात है और सीधे सक्रिय संघर्ष में उलझना दूसरी। फिलहाल उन दोनों की खुद की स्थिति से भी ऐसा नहीं लगता। रूस में पुतिन वैधता और साख अर्जन की आंतरिक लड़ाई लड़ रहे है तो चीन नेतृत्व परिवर्तन को प्रमुखता दे रहा है।

जो ईरान स्वयं विश्व का ज्वलनांक बना हुआ है, वह असद की रक्षा नहीं कर सकता लेकिन गहराई से देखें तो सीरिया के संकट ने शीतयुद्ध की दो पूर्व शक्तियों के बीच नई तनावपूर्ण प्रतिद्वंद्विता तथा शिया–सुन्नी समुदायों के नेतृत्वकारी शक्तियों के बीच क्षेत्रीय प्रभाव के लिए तीखे युद्ध को रेखांकित किया है। शिया नेतृत्व वाला ईरान बशर का पक्का समर्थक है। सीरिया की सुरक्षा सेवाओं पर वर्चस्व रखने वाला अल्पसंख्यक अलावित संप्रदाय शिया इस्लाम का अंग है। इसके विपरीत सुन्नी बहुल देश सऊदी अरब असद की विदाई चाहता है।

अब सुन्नी वर्चस्व वाले कतर के शासक ने सऊदी अरब के साथ खड़ा होते हुए विद्रोहियों को हथियार सहित अन्य संसाधन मुहैया कराने का समर्थन किया है। गौरतलब है कि सीरियाई विद्रोहियों में ज्यादातर सुन्नी बहुमत के लोग ही हैं। इससे एक ऐसे छायायुद्ध की संभावना पैदा हो रही है, जिसमें एक ओर सऊदी अरब एवं कतर के समर्थन से संघर्षरत विद्रोही होंगे तो दूसरी ओर रूस व ईरान द्वारा समर्थित असद की सेना होगी। सीरिया में लगभग एक साल से असद के खिलाफ विद्रोह और संघर्ष चल रहा है। लोकल कोऑर्डिनेशन कमेटी, जो कि विरोध प्रदर्शनों का आयोजन तथा उनका दस्तावेजीकरण करती है, की बात मानी जाए तो कम से कम पांच हजार निरपराध लोग सरकारी हिंसा में मारे गए हैं।

हालांकि इसकी स्वतंत्र और मान्य पुष्टि कठिन है। देश के उत्तरी हिस्से में विरोधियों की ताकत ज्यादा है। इसलिए सेना का हमला उधर ज्यादा हो रहा है। वहां सेना ज्यादातर समय लक्ष्य बनाकर हमला करने के बजाय कई बार यत्र–तत्र बमवर्षा करती है, जिसमें कोई भी हताहत हो सकता है। सरकार विरोधियों पर अंतरराष्ट्रीय सहानुभूति के लिए लोगों की हत्या करने का आरोप लगाती है।

जनमत संग्रह के दिन हुई हिंसा में एक अमेरिकी पत्रकार मारा गया तथा घायल होने वालों में ब्रिटेन का एक पत्रकार एवं फ्रांस का एक फोटो पत्रकार भी शामिल था। स्थिति कितनी विकट रही होगी, इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि रेडक्रॉस की टीम सारी क्षमता लगाकर भी उन दोनों को उस दिन बाहर नहीं निकाल सकी। विद्रोहियों द्वारा जनमत संग्रह को नकारने तथा उन्हें पश्चिमी देशों के समर्थन के कारण हिंसा अभी रुकने वाली नहीं।

हालांकि प्रतिबंधों के कारण सीरिया की समस्याएं बढ़ रहीं हैं पर न असद आसानी से इस्तीफा देने वाले हैं और न पश्चिम इस संविधान को मान्यता देने वाला है। यानी टकराव बढ़ना निश्चित है। रूस और चीन, सीरिया के खिलाफ सुरक्षा परिषद के किसी प्रस्ताव को पुनः वीटो करेंगे। इससे तनावपूर्ण प्रतिद्वंद्विता और गहरी होगी।

वास्तव में विश्व का भला इसी में है कि सीरिया और ईरान संकट का समाधान जल्द हो लेकिन निकट भविष्य में इसकी संभावना नहीं दिखती। जाहिर है हितों परस्पर संघर्ष हल निकलने में आड़े आ रहा है। अब तो व्यापक मोर्चे वाले हितों से ही समाधान पर एकजुट होने की उम्मीद है। यह कोई नहीं बता सकता कि ऐसी स्थिति कब आएगी?

गहराई से देखें तो सीरिया के संकट ने शीतयुद्ध की दो पूर्व शक्तियों के बीच नई तनावपूर्ण प्रतिद्वंद्विता तथा शिया–सुन्नी समुदायों के नेतृत्वकारी शक्तियों के बीच क्षेत्रीय प्रभाव के लिए तीखे युद्ध को रेखांकित किया है जनमत संग्रह को विद्रोहियों के नकारने तथा उन्हें पश्चिमी देशों के समर्थन के कारण हिंसा अभी रुकने वाली नहीं। प्रतिबंधों के कारण सीरिया की समस्याएं बढ़ रहीं हैं पर न असद आसानी से इस्तीफा देने वाले हैं और न पश्चिम इस संविधान को मान्यता देने वाला है। ❑

उपलब्धियों से वंचित ब्रिक्स

एक ऐसे समय जब चीन पर निर्यात प्रतिस्पर्धा के लिए अपनी मुद्रा का मूल्य बढ़ाने का दबाव है, ब्रिक्स संरचना इसे अपनी मुद्रा के अंतराष्ट्रीय भूमिका के विस्तार का अवसर सुलभ कराती है। वैश्विक मुद्रा के रूप में डॉलर या यूरो को अपदस्थ करने के लिए चीन ब्रिक्स देशों को रैनमिंबी ऋण उपलब्ध करा सकता है। रैनमिंबी में ऋण लेने और व्यापार करने से चीन की अंतरराष्ट्रीय हैसियत बढ़ेगी। किंतु इसकी अवमूल्यित मुद्रा और छिपे हुए निर्यात अनुदान से अन्य ब्रिक्स देशों के घरेलू उत्पादन पर नजला गिर रहा है, खासतौर पर भारत व ब्राजील पर।

■ ब्रह्म चेलानी

ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का समूह ब्रिक्स समान पहचान और सहयोग के संस्थानीकरण की तलाश में जुटा है। यह लक्ष्य हासिल करना कठिन है क्योंकि इन देशों की राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय लक्ष्यों में भारी अंतर है। साथ ही ये देश विश्व के अलग–अलग कोनों में स्थित हैं। फिर भी, पहली महत्वपूर्ण गैर–पश्चिमी वैश्विक पहल के लिए ब्रिक्स समूह सराहना का पात्र है। सदस्यों में साझा धरातल के अभाव के कारण कुछ आलोचक ब्रिक्स को ईंटों के ढेर के नाम से संबोधित करने लगे हैं।

हालांकि इसके पक्षकार इसे वर्तमान वैश्विक शक्ति परिवर्तन का उत्पाद बता रहे हैं। उनका मानना है कि इसमें वैश्विक शासन को आकार देने का प्रमुख उपकरण बनने की संभाव्यता है।

दूसरे शब्दों में, ब्रिक्स नई वैश्विक व्यवस्था के गठन में प्रमुख भूमिका निभा सकता है। ईरान और सीरिया जैसे ज्वलंत मुद्दों पर ब्रिक्स संयम और सावधानी बरत रहा है। यह पश्चिमी ताकतों की दखलवादी आवेग में संतुलन लाने को प्रयासरत है। किंतु श्रीलंका पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रस्ताव से यह साफ हो गया है कि अन्य मुद्दों पर समूह बुरी तरह बंटा हुआ है, खासतौर पर जहां चीन के व्यापारिक और सामरिक हित सधते हों। आर्थिक रूप से ब्रिक्स वैश्विक विकास का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है।

आखिरकार ब्रिक्स समूह विश्व के चौथाई भूभाग से अधिक हिस्से, 41 फीसदी से अधिक आबादी का प्रतिनिधित्व करता है और 25 फीसदी से अधिक

आखिरकार ब्रिक्स समूह विश्व के चौथाई भूभाग से अधिक हिस्से, 41 फीसदी से अधिक आबादी का प्रतिनिधित्व करता है और 25 फीसदी से अधिक जीडीपी तथा करीब आधे विदेशी मुद्रा व स्वर्ण भंडार में योगदान देता है। इतिहास का चक्र उलटा चलने लगा है और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं अपने वृहद विदेशी मुद्रा भंडार के बल पर अब संपन्न अर्थव्यवस्थाओं के घाटे को पाट रही हैं। इस आलोक में अगर ब्रिक्स एकजुट होकर काम करे तो वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में मजबूत ताकत बन सकता है।

जीडीपी तथा करीब आधे विदेशी मुद्रा व स्वर्ण भंडार में योगदान देता है। इतिहास का चक्र उलटा चलने लगा है और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं अपने वृहद विदेशी मुद्रा भंडार के बल पर अब संपन्न अर्थव्यवस्थाओं के घाटे को पाट रही हैं। इस आलोक में अगर ब्रिक्स एकजुट होकर काम करे तो वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में मजबूत ताकत बन सकता है।

ब्रिक्स देशों की मुद्रा–रियल, रूबल, रुपया, रैनमिंबी और रैंड के पहले अक्षर के आधार पर इस समूह को आर–5 का नाम भी दिया जा सकता है। नई दिल्ली सम्मेलन में ब्रिक्स समूह के नेता संयुक्त संस्थानों के गठन पर किया। खासतौर पर साझा विकास बैंक के गठन पर जो देशों की बचत का प्रबंधन किया। फिलहाल, ब्रिक्स एक ढीलाढाला और अनौपचारिक गुट है। अगर समूह के नेता संस्थागत ढांचा बनाने की दिशा में आगे बढ़ने में विफल रहते हैं तो वे इस अवधारणा को मजबूत ही करेंगे कि यह महज गपबाजी का अड्डा है, क्योंकि इन देशों के साझा हितों में इतनी विविधता है कि इन्हें साझा योजना के तहत पूरा करना संभव ही नहीं है।

पिछले साल ही ब्राजील, रूस, भारत और चीन के संगठन ब्रिक में दक्षिण अफ्रीका को शामिल करने से इसने ब्रिक्स का रूप लिया है। 2009 में रूस में ब्रिक का पहला सम्मेलन हुआ। ब्रिक के ब्रिक्स के रूप में विस्तार के बाद से और वैश्विक समूहों का गठन हुआ है, जिससे इन समूहों के एकदूसरे की पहल को अप्रासंगिक बनाने का खतरा खड़ा हो गया है। इसी प्रकार का एक समूह है आइबीएसए। इसमें भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं।

पिछले साल ही ब्राजील, रूस, भारत और चीन के संगठन ब्रिक में दक्षिण अफ्रीका को शामिल करने से इसने ब्रिक्स का रूप लिया है। 2009 में रूस में ब्रिक का पहला सम्मेलन हुआ। ब्रिक के ब्रिक्स के रूप में विस्तार के बाद से और वैश्विक समूहों का गठन हुआ है, जिससे इन समूहों के एकदूसरे की पहल को अप्रासंगिक बनाने का खतरा खड़ा हो गया है। इसी प्रकार का एक समूह है आइबीएसए। इसमें भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं।

ब्राजील, रूस, भारत और दक्षिण अफ्रीका के लिए ब्रिक्स समूह अपनी उभरती हुई आर्थिक ताकत को रेखांकित करने और वैश्विक खिलाड़ियों में अपनी भूमिका को निखारने का जरिया है। किंतु चीन को उभरती हुई विश्व शक्ति के रूप में पहचान बनाने की कोई जरूरत नहीं है। चीन के लिए ब्रिक्स की अहमियत प्रतीकात्मक न होकर मूर्त लाभ उठाने के रूप में है। परिणामस्वरूप चीन पूरे समूह पर अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहता है। उदाहरण के लिए यह प्रस्तावित साझा विकास बैंक पर अपना नियंत्रण चाहता है, जिसके लिए भारत और रूस तैयार नहीं हैं।

एक ऐसे समय जब चीन पर निर्यात प्रतिस्पर्धा के लिए अपनी मुद्रा का मूल्य बढ़ाने का दबाव है, ब्रिक्स संरचना इसे अपनी मुद्रा के अंतराष्ट्रीय भूमिका के विस्तार का अवसर सुलभ कराती है। वैश्विक मुद्रा के रूप में डॉलर या यूरो को अपदस्थ करने के लिए चीन ब्रिक्स देशों को रैनमिंबी ऋण उपलब्ध करा सकता है। रैनमिंबी में ऋण लेने और व्यापार करने से चीन की अंतरराष्ट्रीय हैसियत बढ़ेगी। किंतु इसकी अवमूल्यित मुद्रा और छिपे हुए निर्यात अनुदान से अन्य ब्रिक्स देशों के घरेलू उत्पादन पर नजला गिर रहा है, खासतौर पर भारत व ब्राजील पर।

ब्रिक्स अवधारणा के प्रस्तावकों को

अभी भी उम्मीद है कि समूह वैश्विक संस्थागत सुधार का उत्प्रेरक बन सकता है। बीसवीं सदी के मध्य से ही विद्यमान अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाओं में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जबकि इस बीच गैर पश्चिमी आर्थिक शक्तियों और गैरपरंपरागत चुनौतियां मुखर हुई हैं। विश्व अब तक उठाए गए अनमने और असंगत कदमों से कहीं अधिक की अपेक्षा कर रहा है। असल में, वैश्विक शक्ति के बदले संतुलन में जो हल्के–फुल्के कदम उठाए भी गए हैं, वे आर्थिक क्षेत्र तक सीमित रहे हैं और शांति व सुरक्षा कुछ मुट्ठीभर देशों की बपौती बनी हुई हैं।

जब वैश्विक संस्थागत सुधारों की बात आती है तो चीन अन्य ब्रिक्स देशों से अलग खड़ा नजर आता है। यह एक संशोधनवादी शक्ति है, जिसकी निगाह वैश्विक वित्तीय संरचना के निर्माण पर है। चीन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से चली आ रही वित्तीय व्यवस्था को बदलना चाहता है। किंतु संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था के सवाल पर यह यथास्थिति बनाए रखने का पक्षधर है और सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के विस्तार का विरोध करता है। चीन का यह नजरिया भारत के हितों के खिलाफ है। अगर ब्रिक्स देश अंतरराष्ट्रीय संबंधों में दबाव समूह के रूप में विकसित होना चाहते हैं, तो उन्हें ऐसे राजनीतिक व आर्थिक लक्ष्यों पर राजी होना चाहिए, जिन्हें हासिल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, ब्रिक्स देश विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में डॉलर की हैसियत के खिलाफ एकजुट नहीं हैं। असल में, प्रत्येक ब्रिक्स देश के सबसे महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंध अमेरिका के साथ हैं। ब्रिक्स अवधारणा इसके सदस्यों की वैश्विक व्यवस्था को बहुलवादी बनाने की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। किंतु यह निश्चित नहीं है कि ये देश सुनिश्चित लक्ष्यों और संस्थागत तंत्र विकसित करने के लिए परस्पर सहयोगी समूह बन पाएंगे। आने वाले दिनों में हम देख पाएंगे कि क्या ब्रिक्स अपने नाम के अनुरूप महज ईंटों का ढेर बन गया है या फिर अपनी उपयोगिता साबित कर पा रहा है। ❑

सदस्यता संबंधी सूचना

मान्यवर,,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीघ्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है।

स्वदेशी पत्रिका	वार्षिक	आजीवन
हिन्दी	100/–	1000/–
अंग्रेजी	100/–	1000/–

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

पता : **स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22**

आर्थिक विषमता का चिंताजनक दौर

भारत में विभिन्न वर्ग की आय संबंधी नेशनल सैंपल सर्वे के वर्ष 2009–10 के आंकड़ों के अनुसार देश में उच्च वेतन वर्ग तथा निम्न वेतन वर्ग के वेतन में असमानता तेजी से बढ़ रही है। पिछले एक दशक में तेज आर्थिक विकास दर ने उच्च वेतन वर्ग और निम्न वेतन वर्ग के बीच वेतन संबंधी विषमता को बढ़ाया है। यह बिलकुल स्पष्ट है कि भारत की अधिकांश आबादी विकास के लाभ से अब भी वंचित है। नवीनतम सरकारी अध्ययनों में देश के अधिकांश लोगों की अत्यंत कम आमदनी संबंधी चिंताजनक तस्वीर उभरकर सामने आ रही है।

■ जयंतीलाल भंडारी

हाल ही में वित्त राज्यमंत्री द्वारा राज्यसभा में दी गई इस जानकारी को पूरा देश विस्मित होकर देख रहा है कि भारत के 8200 सर्वाधिक अमीर लोगों के पास करीब 47250 अरब रुपए की दौलत है, जो देश की अर्थव्यवस्था का करीब 70 प्रतिशत हिस्सा है।

सरकार के द्वारा यह जानकारी ग्लोबल वेल्थ इंटेलीजेंस फर्म 'वैल्थ' द्वारा कराए गए ताजा सर्वेक्षण में हुए खुलासे पर आधारित है। निसंदेह वर्ष 1991 से आर्थिक विकास के रास्ते पर तेज दौड़ लगाने के बावजूद भारत में आर्थिक विषमता दुनिया के देशों की तुलना में सबसे अधिक बढ़ी है। भारत में आर्थिक विषमता के संबंध में प्रकाशित विभिन्न शोध अध्ययनों में कहा गया है कि यद्यपि भारत में प्रति व्यक्ति आय लगातार बढ़ रही है लेकिन यह देश की राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग देने से प्राप्त औसत मात्र है। यह सभी लोगों के समृद्ध होने का प्रतीक नहीं है। इतना ही नहीं मुद्रा प्रसार के कारण रुपए की क्रय शक्ति में भारी कमी आई है।

वस्तुतः आर्थिक विकास का लाभ कुछ ही मुट्ठियों में बंद होकर रह गया है। देश में न केवल अमीरी और गरीबी के बीच असमानता तेजी से बढ़ी है, वरन वेतन असमानता भी बढ़ी है। हाल ही में ख्याति प्राप्त वैश्विक प्रबंधन सलाहकार फर्म 'हे ग्रुप' ने 'इन टॉप एक्जीक्यूटिव कंपनसेशन रिपोर्ट' में कहा है कि वित्त वर्ष 2011–12 में देश में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) का औसत वेतन दो करोड़ रुपए से अधिक रहा।

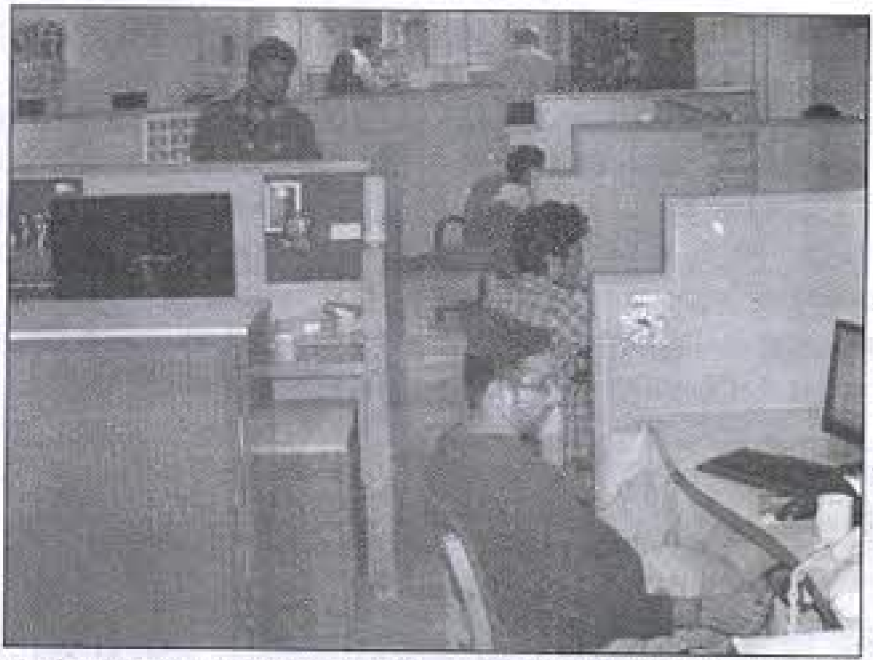

रिपोर्ट में कहा गया है कि उद्योग जगत के सीईओ और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन में भी काफी अंतर है। वर्ष 2011–12 में अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के औसत वेतन की तुलना में सीईओ का औसत वेतन 2.6 गुना अधिक रहा। यह निष्कर्ष निकालने के लिए 'हे ग्रुप' ने विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी 87 कंपनियों के सीईओ व अन्य वरिष्ठ

यकीनन, भारत में वेतन विषमता का परिदृश्य यह भी बता रहा है कि निजी क्षेत्र में वेतन विषमता अधिक बढ़ी है, जबकि सरकारी क्षेत्र में वेतन विषमता कम है। सरकारी क्षेत्र में शासन की नीतियों को कार्यान्वित करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने वाले सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी सरकार के चीफ सेक्रेटरी और सरकार के तृतीय श्रेणी कर्मचारी के वेतन में निजी क्षेत्र की तरह वेतन की भारी विषमताएं नहीं हैं।

मार्च, 2012 में प्रकाशित कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश के 65 फीसद किसानों की आमदनी रोजाना 20 रुपए भी नहीं है। मार्च, 2012 में प्रकाशित एक अन्य अध्ययन रिपोर्ट में पाया गया है कि योजना आयोग ने वर्ष 2009–10 के लिए ग्रामीण इलाकों में प्रतिदिन 22.40 रुपये और शहरी क्षेत्र में 28.64 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से गरीबी रेखा तय कर दी है जो उपयुक्त नहीं है।

अधिकारियों के वेतन पैकेज और उनके कामकाज का अध्ययन किया।

देश की शीर्ष कंपनियों से संबंधित एक महत्वपूर्ण अध्ययन से मालूम हुआ है कि कारोबारी साल 2009–10 में शीर्ष कंपनियों के सीईओ ने अपनी कंपनियों के औसत कर्मचारियों के वेतन की तुलना में 68 गुना अधिक वेतन लिया। जबकि 2008–09 में उनका वेतन औसत कर्मचारियों के वेतन का 59 गुना था। जहां कारपोरेट हस्तियां अपने घर ज्यादा से ज्यादा वेतन ले जाकर धन कुबेर का प्रतीक बन रही हैं, वहीं बाकी स्टॉफ का वेतन असंतोषजनक अनुभव किया जा रहा है। यकीनन, भारत में वेतन विषमता का परिदृश्य यह भी बता रहा है कि निजी क्षेत्र में वेतन विषमता अधिक बढ़ी है, जबकि सरकारी क्षेत्र में वेतन विषमता कम है। सरकारी क्षेत्र में शासन की नीतियों को कार्यान्वित करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने वाले सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी सरकार के चीफ सेक्रेटरी और सरकार के तृतीय श्रेणी कर्मचारी के वेतन में निजी क्षेत्र की तरह वेतन की भारी विषमताएं नहीं हैं। जहां चीफ सेक्रेटरी को वेतन व महंगाई भत्ते (डीए) के रूप में कोई 15 लाख रुपए वार्षिक प्राप्त होते हैं, वहीं औसतन सरकार के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को ढाई लाख रुपए वार्षिक प्राप्त होते हैं।

शासन के उच्चतम अधिकारी एवं तृतीय श्रेणी कर्मचारी के वेतन के बीच यह अंतर छह गुना ही है। यहां पर दुनिया के प्रमुख संगठन ऑर्गनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक को–ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट (आईसीडी) के द्वारा जारी एक नवीनतम रिपोर्ट का उल्लेख भी प्रासंगिक होगा।

इस रिपोर्ट में बताया गया है कि उदारीकरण के पिछले बीस वर्षों में भारत की वेतन विषमता बढ़कर सीधे दोगुनी हो गई है। 1990 में सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले 10 फीसद भारतीयों की औसत सालाना आय सबसे कम वेतन पाने वाले 10 प्रतिशत लोगों की छह गुनी हुआ करती थी, जो इस समय बारह गुनी हो गई है।

उल्लेखनीय है कि आईसीडी ने ये जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, वे पक्के कागज पर वेतन लेने वाले नौकरीपेशा लोगों की आमदनी से जुड़े हुए हैं। यह महज अनुमान मात्र नहीं हैं।

इतना ही नहीं आईसीडी ने भारत में वेतन विषमता की स्थिति की तुलना भारत की तरह आर्थिक–सामाजिक प्रवृत्तियां रखने वाले तीन देशों– चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका से की है।

निष्कर्ष यह है कि इन तीनों देशों में वेतन विषमता पिछले बीस वर्षों में लगातार कम हुई है। इतना ही नहीं

आईसीडी ने भारत में वेतन विषमता की स्थिति की तुलना भारत की तरह आर्थिक–सामाजिक प्रवृत्तियां रखने वाले तीन देशों – चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका से की है। निष्कर्ष यह है कि इन तीनों देशों में वेतन विषमता पिछले बीस वर्षों में लगातार कम हुई है। इतना ही नहीं चीन में सबसे गरीब 20 फीसदी लोगों की आमदनी पिछले दो दशकों में वहां के सबसे अमीर 20 फीसदी लोगों की तुलना में दोगुनी रफ्तार से बढ़ी है। इस प्रकार हम वेतन विषमता की दृष्टि से अमेरिकी और यूरोपीय परंपरा की ओर बढ़ रहे हैं।

चीन में सबसे गरीब 20 फीसदी लोगों की आमदनी पिछले दो दशकों में वहां के सबसे अमीर 20 फीसदी लोगों की तुलना में दोगुनी रफ्तार से बढ़ी है। इस प्रकार हम वेतन विषमता की दृष्टि से अमेरिकी और यूरोपीय परंपरा की ओर बढ़ रहे हैं।

अमेरिकी थिंक टैंक इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज ने अमेरिका में 500 कंपनियों के अध्ययन में यह पाया है कि अमेरिका में शीर्ष एग्जिक्यूटिव, अपने औसत कर्मचारी की तुलना में 263 गुना वेतन व बोनस प्राप्त करते हैं। यह फर्क 1980 के दशक से लगातार बढ़ रहा है। अब यूरोप में भी कारपोरेट आमदनी में लगातार असमानता बढ़ रही है।

लंदन स्टॉक एक्सचेंज के बेंचमार्क इंडेक्स 'एफटीएसई–100' में शामिल कंपनियों के मामले में सीईओ की तनख्वाह और औसत कर्मचारी की तनख्वाह के बीच जो अंतर 1998 में 47 गुना था, वह 2009 में बढ़कर 115 गुना तक पहुंच गया।

भारत में विभिन्न वर्ग की आय संबंधी नेशनल सैंपल सर्वे के वर्ष 2009–10 के आंकड़ों के अनुसार देश में उच्च वेतन वर्ग तथा निम्न वेतन वर्ग के वेतन में असमानता तेजी से बढ़ रही है। पिछले एक दशक में तेज आर्थिक विकास दर ने उच्च वेतन वर्ग और निम्न वेतन वर्ग के बीच वेतन संबंधी विषमता को बढ़ाया है। यह बिलकुल स्पष्ट है कि भारत की अधिकांश आबादी विकास के लाभ से अब भी वंचित है। नवीनतम सरकारी अध्ययनों में देश के अधिकांश लोगों की अत्यंत कम आमदनी संबंधी चिंताजनक तस्वीर उभरकर सामने आ रही है।

मार्च, 2012 में प्रकाशित कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश के 65 फीसद किसानों की आमदनी रोजाना 20 रुपए भी नहीं है। मार्च, 2012 में प्रकाशित एक अन्य अध्ययन रिपोर्ट में पाया गया है कि योजना आयोग ने वर्ष 2009–10 के लिए ग्रामीण इलाकों में प्रतिदिन 22.40 रुपये और शहरी क्षेत्र में 28.64 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से गरीबी रेखा तय कर दी है जो उपयुक्त नहीं है।

योजना आयोग दावा करता है कि पिछले पांच वर्षों में 7.4 फीसद लोग गरीबी से ऊपर उठ गए हैं। वास्तव में इस समय देश की सच्ची आर्थिक–सामाजिक खुशहाली के लिए हमें आर्थिक विषमता की बढ़ती हुई खाई को कम करना होगा। यदि हमें देश के सभी लोगों को अच्छी जिंदगी की सौगात देनी है तो इसके लिए जरूरी होगा कि आम आदमी और गरीबों की खुशहाली से जुड़ी रोजगार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर गंभीरता से ध्यान केंद्रित किया जाए। जहां कारपोरेट जगत के द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व और नैतिक प्रतिबद्धता को स्वीकार किया जाना चाहिए। वहीं सरकार को यह भी ध्यान रखना होगा कि वह आय और धन के वितरण की भारी असमानता को मिटाने के परिप्रेक्ष्य में कमजोर वर्ग के लोगों की आय बढ़ाने के कारगर प्रयास करे।

ऐसे में सरकार के द्वारा गरीबों की योजनाओं से सभी गरीबों को व्यावहारिक रूप से लाभान्वित करके उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कारगर प्रयास जरूरी हैं। भारत में उदारीकरण का एक उद्देश्य न्यायपूर्ण समाज का निर्माण भी है। इसलिए सरकार द्वारा वेतन की असमानता कम करने के लिए चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की न्याय संगत वेतन नीतियों की तरह कारगर उपाय किए जाने चाहिए। ताकि कम वेतन वाले लाखों लोगों को संतोषजनक वेतन मिल सके। इसके साथ ही कम योग्य युवाओं के लिए हमें प्रशिक्षण एवं सेवा क्षेत्र में अवसर खोजने होंगे और उन्हें रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों से शिक्षित–प्रशिक्षित करना होगा।

गांवों में काफी संख्या में जो गरीब, अशिक्षित और अर्धशिक्षित हैं, उन्हें अर्थपूर्ण रोजगार देने के लिए कौशल प्रशिक्षण से सुसज्जित करके निम्न तकनीक विनिर्माण में लगाना होगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार देश में बढ़ती हुई आर्थिक विषमता के खतरों और चुनौतियों को समझते हुए इसे कम करने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी। ❑

मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ

यहां मूल प्रश्न यह है कि क्या इस तरह के गोपनीय पत्रों का छपते रहना राष्ट्रहित में है? क्या मीडिया को इतनी छूट दी जानी चाहिए? क्या किसी अखबार या टीवी चैनल को उसकी खबर का स्त्रोत बताने के लिए मजबूर किया जा सकता है? अंग्रेज के जमाने में तो मजबूर किया जा सकता था। बांग्ला पत्रिका 'हितबादी' के संपादक कालिप्रसन्न काव्यबिशारद और 'वंदे मातरम' के संपादक विपिनचंद्र पाल इसी कारण जेल काट चुके थे। उन्होंने मुद्रित सामग्री के लेखक का नाम उजागर करने से मना कर दिया था। हमारे उच्च न्यायालयों ने अभी तक उसी परंपरा को बरकरार रखा है। दो–तीन मामलों में उन्होंने स्त्रोत उजागर करने को उचित ठहराया है लेकिन उच्चतम न्यायालय ने अभी तक इस बारे में कोई ठोस राय जाहिर नहीं की है।

■ वेद प्रताप वैदिक

प्रधानमंत्री को लिखे गए सेना–प्रमुख के पत्र का रहस्य अभी तक नहीं खुल पाया है। वह गोपनीय पत्र अखबार तक कैसे पहुंचा, इसका पता लगाने में सरकार असमर्थ दिखाई पड़ रही है।

प्रधानमंत्री को लिखे गए सेना–प्रमुख के पत्र का रहस्य अभी तक नहीं खुल पाया है। वह गोपनीय पत्र अखबार तक कैसे पहुंचा, इसका पता लगाने में सरकार असमर्थ दिखाई पड़ रही है। यों तो इस रहस्य का पता लगाना बिल्कुल आसान है। जिस पत्रकार ने वह पत्र 'लीक' किया है, उसका नाम अखबार के मुखपृष्ठ पर छपा है। उसे सरकार पकड़ ले और उससे सब कुछ उगलवा ले लेकिन क्या सरकार ऐसा कर सकती है?

ऐसा करने से कोई भी सरकार बहुत डरेगी, क्योंकि देश के सारे पत्रकार उसके खिलाफ हो जाएंगे। जैसे सरकार विधानपालिका और न्यायपालिका को नाराज करने का खतरा मोल नहीं ले सकती, वैसे ही वह खबरपालिका को भी नाराज नहीं कर सकती। इसके अलावा सेना–प्रमुख के गोपनीय पत्र के 'लीक' हो जाने से भारत की कोई सीधी हानि नहीं हुई है। यदि आजकल कोई युद्धकाल होता तो यह पत्र काफी खतरनाक सिद्ध हो सकता था। दुश्मन हमारी फौजी कमजोरियों का फायदा उठा सकता था लेकिन उल्टे, उस पत्र के छपने से हमारी सुरक्षा–व्यवस्था को कुछ न कुछ फायदा ही होगा।

यहां मूल प्रश्न यह है कि क्या इस तरह के गोपनीय पत्रों का छपते रहना राष्ट्रहित में है? क्या मीडिया को इतनी छूट दी जानी चाहिए? क्या किसी अखबार या टीवी चैनल को उसकी खबर का स्त्रोत बताने के लिए मजबूर किया जा सकता है? अंग्रेज के जमाने में तो मजबूर किया जा सकता था। बांग्ला पत्रिका 'हितबादी' के संपादक कालिप्रसन्न काव्यबिशारद और 'वंदे मातरम' के संपादक विपिनचंद्र पाल इसी कारण जेल काट चुके थे। उन्होंने मुद्रित सामग्री के लेखक का नाम उजागर करने से मना कर दिया था। हमारे उच्च न्यायालयों ने अभी तक उसी परंपरा को बरकरार रखा है। दो–तीन मामलों में उन्होंने स्त्रोत उजागर करने को उचित ठहराया है लेकिन उच्चतम न्यायालय ने अभी तक इस बारे में कोई ठोस राय जाहिर नहीं की है।

इस मामले में न तो पूरी छूट देना उचित है और न ही पूर्ण प्रतिबंध लगाना। मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। केवल उन खबरों का स्त्रोत उजागर करना जरूरी होना चाहिए, जिनसे देश की सुरक्षा को खतरा हो, आंतरिक दंगे भड़क सकते हों या किसी देश के साथ संबंध खराब हो सकते हों। आजकल का ब्रिटिश कानून लगभग ऐसा ही है। फ्रांस में पूरी छूट है और अमेरिका बड़ा छुई–मुई है। ये दोनों ही अतिवाद हैं।

भारत भी अतिवाद के रास्ते पर चलना चाहता है। वरना उस पत्र की 'लीक' पर 'देशद्रोह', 'देशद्रोह' चिल्लाने की जरूरत क्या थी? वह या तो एंटनी–द्रोह था या वी.के. सिंह–द्रोह! था वह, बहुत गलत लेकिन वह देशद्रोह कैसे था? मजेदार बात यह है कि उस 'लीक' पर अब सभी चुप्पी साधे हुए हैं।

क्या कोई अखबारवाला ही अब उस 'लीक' के स्त्रोत को भी 'लीक' करेगा? ❑

उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव –2012

सपा के अखिलेश यादव को जनाकांक्षाओं पर स्वयं को सिद्ध करना पड़ेगा

चुनाव के दौरान सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव व उनके पुत्र अखिलेश यादव ने जिस प्रकार चुनावी वायदे किये उस समय हो सकता है उन्हें इतनी विशाल जीत की आशा ही नहीं हो और अब इन वायदों को पूरा करना सपा के गले की हड्डी साबित हो क्योंकि उन वायदों को पूरा करते करते प्रदेश के राजस्व पर बुरा प्रभाव तो पड़ेगा ही बल्कि प्रदेश के विकास पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा व विकास रुक जाने का खतरा पैदा हो जायेगा। इन चुनाव परिणामों ने स्वर्णिम अवसर सपा को प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए दिया है। अतः नयी सोच के धनी अखिलेश यादव को पुरानी जातिगत, सांप्रदायिक व क्षेत्रीय राजनीतिक प्रतिबद्धताओं से ऊपर उठ कर एक नये विकसित व समृद्ध प्रदेश की नींव रखनी होगी।

■ डॉ. सूर्यप्रकाश अग्रवाल

उत्तरप्रदेश विधानसभा के 2012 में सम्पन्न हुए चुनावों में जिस प्रकार प्रदेश की जनता ने विधानसभा की कुल 403 सीटों में 224 सीटों को सपा को सौंप कर जिस प्रकार प्रदेश की जनता ने अपना असीम विश्वास सपा में व्यक्त किया है उसे सपा व उसके नेता विशेष कर नवनिर्वाचित युवा मुख्यमंत्री अखिलेष यादव की जिम्मेदारी प्रदेश की जनता के प्रति बहुत बढ़ गई है और सपा को अपनी पुरानी परिपाटी छोड़ कर एक नये कलेवर, अंदाज व सोच के साथ समस्त प्रदेशवासियों का ध्यान रखते हुए स्वंय को जनता की जनाकांक्षाओं पर सिद्ध करना पड़ेगा।

सपा को स्वयं को सिद्ध करने के लिए केवल वर्ष 2014 तक के लोकसभा के चुनावों तक का ही समय मिल पाया है और यदि सपा जनाकांक्षाओं पर खरी नहीं उतरी तो हो सकता है कि लोकसभा में सपा को प्रदेश की जनता नकार दे और हो सकता है उत्तरप्रदेश में मध्यावधि चुनावों की मांग उत्पन्न हो जाय अथवा वर्ष 2017 में चुनावों में उसको उसी प्रकार बेदखल होना पड़े जिस प्रकार इस समय बसपा की मायावती एक दम से सत्ताच्युत

किसान इस कर्ज माफी के लिए मुलायम सिंह यादव पर अभी से ही दबाब बनायेगें और इसका परिणाम यह निकलेगा कि जो किसान लोग बैंक व सरकारी एजेंसियों से ऋण लेते है उनकी नीयत ऋण को चुकाने की कमी नहीं रहेगी और ऋणी किसान सपा के राजनेताओं पर दबाब बनाते रहेंगे कि उनके ऋण शीघ्र अतिशीघ्र माफ करवा दिये जायें तभी उनको वोट देने का फायदा होगा।... अच्छा होता कि किसानों को मुनासिब दामों पर बीज, पानी, खाद, कीटनाशक दवाईयां व अन्य पदार्थ उपलब्ध करवाये जाते और कृषि उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश की जाती।

हुई है।

अभी मायावती ने हिम्मत दिखाते हुए यह कह कर कि 70 प्रतिशत मुसलमानों ने सपा को वोट दिया व सवर्णों के वोट बंट गये जिस कारण सपा विजयी हो गई है अपना विश्लेषण प्रस्तुत कर दिया। अब यदि सपा मुसलमानों को रिझाने में ही लगी रही तो उसकी प्रतिक्रिया हिन्दुओं में होनी भी स्वाभाविक होगी और मुलायम सिंह यादव की छवि पुनः मुलायम सिंह यादव की उभर आयेगी और अखिलेश

सपा ने चुनाव के दौरान वर्ष 2011 में इंटर की परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले 15.90 लाख छात्र थे जिनको लैपटाप देने का वायदा किया गया है। अब यदि लैपटाप की कीमत 10,000 रुपये की हो तो लैपटाप पर 15.90 अरब रुपये की आवश्यकता होगी। वर्ष 2011 में हाईस्कूल में 22.93 लाख छात्र उत्तीर्ण हुए जिनको टेबलेट (आकाश) देने का वायदा किया है। अब यदि कम से कम एक टेबलेट पर 1,000 रुपये का व्यय होता हो तो 2.29 अरब रुपये का राजस्व पर भार पड़ेगा।

यादव को उससे हानि ही पंहुच सकती है।

इस चुनाव के दौरान सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव व उनके पुत्र अखिलेश यादव ने जिस प्रकार चुनावी वायदे किये उस समय हो सकता है उन्हें इतनी विशाल जीत की आशा ही नहीं हो और अब इन वायदों को पूरा करना सपा के गले की हड्डी साबित हो क्योंकि उन वायदों को पूरा करते करते प्रदेश के राजस्व पर बुरा प्रभाव तो पड़ेगा ही बल्कि प्रदेश के विकास पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा व विकास रुक जाने का खतरा पैदा हो जायेगा।

इन चुनाव परिणामों ने स्वर्णिम अवसर सपा को प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए दिया है। अतः नयी सोच के धनी अखिलेश यादव को पुरानी जातिगत, सांप्रदायिक व क्षेत्रीय राजनीतिक प्रतिबद्धताओं से ऊपर उठ कर एक नये विकसित व समृद्ध प्रदेश की नींव रखनी होगी।

एक अनुमान के मुताबिक सपा के द्वारा चुनावों में जो वायदे किये गये हैं उनको पूरा करने में लगभग 660 अरब रुपये की विशाल धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी। प्रदेशवासी जल्दी से जल्दी इन वायदों को पूरा करने के लिए दबाब भी बनायेगें क्योंकि उनके वायदे से लोगों में एक प्रकार की भिक्षुक प्रवृत्ति व संस्कृति जरुर उत्पन्न हो गई है, ऐसा प्रतीत होता है। मुलायम सिंह यादव के द्वारा किसानों के 50,000 रुपये तक के ऋण माफ करने से राजस्व पर लगभग 110 अरब रुपये का भार पड़ेगा।

किसान इस कर्ज माफी के लिए मुलायम सिंह यादव पर अभी से ही दबाव बनायेगें और इसका परिणाम यह निकलेगा कि जो किसान लोग बैंक व सरकारी एजेंसियों से ऋण लेते हैं उनकी नीयत ऋण को चुकाने की कभी नहीं रहेगी और ऋणी किसान सपा के राजनेताओं पर दबाब बनाते रहेंगे कि उनके ऋण शीघ्र अतिशीघ्र माफ करवा दिये जायें तभी उनको वोट देने का फायदा होगा।

सपा की इस ऋण माफी योजना से बैंक भी अब भविष्य में किसानो को ऋण देने में कौताही करेगें जिससे किसानों को आर्थिक तंगी हो अच्छा हो सकती है। अच्छा होता कि किसानों को मुनासिब दामों पर बीज, पानी, खाद, कीटनाशक दवाईयां व अन्य पदार्थ उपलब्ध करवाये जाते और कृषि उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश की जाती। सपा ने बुनकरों (जिनमें अधिकतर मुसलमान है) व किसानो को मुफ्त बिजली देने का प्रमुख वायदा किया है जिसको पूरा करने में 16.50 अरब रुपये का अनुमान का भार प्रदेश के राजस्व पर पड़ेगा। बिजली मुफ्त मिलेगी यह बात जानकर बिजली को खर्च करने में अपव्ययिता बढ़ जाती है और यूपी पावर कारपोरेशन लिमिटेड को भारी घाटा होने की आशा हो जाती है जिससे प्रदेश में भविष्य में बिजली की समस्या और बढ़ने की उम्मीद हो जाती है जिससे प्रदेश में अंशाति का ही बोलबाला होगा। मुफ्त सिंचाई उपलब्ध कराने पर 5.89 अरब

रुपये का भार राजस्व पर पडता है वैसे तो किसानों की सिंचाई के पानी की आपूर्ति निजी ट्यूबवैलों के द्वारा 77 प्रतिशत तक कर ली जाती है और 23 प्रतिशत पर ही राजस्व पर 5.89 अरब रुपये का अतिरिक्त भार पडता है।

इसी प्रकार वर्ष 2011 में इंटर की परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले 15.90 लाख छात्र थे जिनको लैपटाप देने का वायदा किया गया है। अब यदि लैपटाप की कीमत 10,000 रुपये की हो तो लैपटाप पर 15.90 अरब रुपये की आवष्यकता होगी। वर्ष 2011 में हाईस्कूल में 22.93 लाख छात्र उत्तीर्ण हुए जिनको टेबलेट (आकाष) देने का वायदा किया है। अब यदि कम से क्रम एक टेबलेट पर 1,000 रुपये का व्यय होता हो तो 2.29 अरब रुपये का राजस्व पर भार पडेगा।

छात्र तो 2012 के मार्च माह के प्रारंभ से ही स्कूलों व कालेजों में अध्यापको व प्राचार्यों से पूछताछ करने लगे कि उनको लैपटाप व टेबलेट कब मिलेगा। अब यदि उनको शीघ्र ही लैपटाप व टेबलेट उपलब्ध नहीं करवाये गये तो उनमें असंतोष फैलना भी स्वाभाविक होगा और सपा व उनके नेता युवा पीढी की नजर में धोखेबाज साबित हो जायेगें। अब यदि प्रदेश में चल रहे सीबीएसई व अन्य बोर्डों के द्वारा उत्तीर्ण छात्र भी इसमें शामिल हो गये तो राजस्व पर यह भार और बढ जायेगा।

युवाओं से सपा ने अपने महत्वपूर्ण वायदे में एक वायदा 25 वर्ष से अधिक के बेरोजगारों को 1,000 रुपये महीने का बेरोजगारी भत्ता देने का भी किया था जिस कारण प्रदेश के जिला सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकरण कराने के लिए युवाओं की भीड़ लगना फरवरी माह से ही शुरु हो गई थी। अच्छे अच्छे खाते पीते

पहले भी अन्य प्रदेशों में डेढ़ रुपये किलो चावल, रंगीन टीवी इत्यादि देने के प्रलोभन मतदाताओं को दिया गया था इन प्रलोभनों से राजनीतिक दल चुनाव जीत भी जाते है परन्तु थोडे समय में ही वायदे पूरे न कर पाने के कारण राज्यों में राजनीतिक दलों की छीछालेदर होने लगती है। झूठे व पूरे न होने वाले वायदे से सत्ता प्राप्त करना भी क्या चुनाव आयोग की आचार संहिता में शामिल किया जा सकेगा जिन वायदों के जाल में भोली–भाली जनता फंस जाती है और वोट दे बैठती है। घोषणा पत्र व चुनावी सभाओं में किये गये वायदों को पूरा करने की अनिवार्यता राजनीतिक दल पर लाजमी होनी चाहिए।

घरों के युवा स्वयं को बेरोजगार साबित करने पर उतर आये और अपना बेरोजगार की हैसियत से रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण करवा रहे है।

वायदा यह भी था कि 25 वर्ष की इस आयु को अधिकतम 35 वर्ष की सीमा को बढ़ा दिया जायेगा। पहले भी मुलायम सिंह यादव 2006 में 25–35 वर्ष के आयु के बेरोजगारों को 500 रुपये प्रति मास बेरोजगारी भत्ता दे चुके है। अभी तो आयु सीमाएं पक्के तौर पर नहीं निर्धारित की गई है। अब यदि बेरोजगारी के पुराने आंकडे ले तो 10 अरब रुपये से अधिक का व्यय इस मद पर होगा।

इस प्रकार लगभग 660 अरब रुपये सपा के वायदों को पूरा करने में व्यय होने की उम्मीद है। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि मंहगाई बढ़ चुकी है। वित्त वर्ष 2010–11 में प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 5.68 लाख करोड रुपये तथा राजकोषीय घाटा 189.6 अरब रुपये का था जो जीडीपी का 2.97 प्रतिशत था अतः प्रदेश की जर्जर वित्त व्यवस्था में सपा को अपने वायदे पूरे करने के लिए सरकारी खजाने पर 660 अरब रुपये का अतिरिक्त भार डालना पडेगा।

सपा ने अपने घोषणा पत्र में ऐसी कोई नीति अपनाने का वायदा कदापि नहीं किया है जिससे प्रदेश में राजस्व में वृद्धि हो सके अब केन्द्र से भी किसी सहायता की अपेक्षा कांग्रेस के रहते हुए नहीं की जा सकेगी उल्टे अब प्रदेश सरकार को केंद्र के द्वारा विभिन्न योजनाओं पर आयी रकमों का भी हिसाब देना पडेगा जिनके कई अरब रुपये की लेनदारी निकल सकती है सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों को मायावती की सरकार में मुफ्त का खाने की आदत पड चुकी है। अब पत्थरों के हाथियों व मूर्तियों को बेच कर तो घाटा पूरा नहीं किया जा सकता है।

पहले भी अन्य प्रदेशों में डेढ रुपये किलो चावल, रंगीन टीवी इत्यादि देने के प्रलोभन मतदाताओं को दिया गया था इन प्रलोभनों से राजनीतिक दल चुनाव जीत भी जाते है परन्तु थोडे समय में ही वायदे पूरे न कर पाने के कारण राज्यों में राजनीतिक दलों की छीछालेदर होने लगती है। झूठे व पूरे न होने वाले वायदे से सत्ता प्राप्त करना भी क्या चुनाव आयोग की आचार संहिता में शामिल किया जा सकेगा जिन वायदों के जाल में भोली–भाली जनता फंस जाती है और वोट दे बैठती है। घोषणा पत्र व चुनावी सभाओं में किये गये वायदों को पूरा करने की अनिवार्यता राजनीतिक दल पर लाजमी होनी चाहिए। ❑

गंगा के प्रति शून्य संवेदना

गंगा भारतीय संस्कृति, सभ्यता, अस्मिता का प्रतीक है। भारत की दो–तिहाई खेती का प्राणाधार है। उसे राष्ट्रीय नदी घोषित करने की जरूरत क्या थी? पहली बात तो यह कि हमने गंगा के लिए सिर्फ राष्ट्रीय नदी का दर्जा नहीं मांगा था, हमने तो गंगा को राष्ट्रीय नदी प्रतीक घोषित करने की मांग की थी। एक ऐसी ढांचागत व्यवस्था की मांग की थी, ताकि गंगा संरक्षण की जवाबदेही राज्य व केंद्र के बीच में न फंसे। हमने चाहा था कि गंगा संरक्षण के कार्य व निर्णय भिन्न विभागों के बीच तालमेल के अभाव व सरकारों की टालमटोल से मुक्त हों। उन्होंने सिर्फ राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया और एक प्राधिकरण बनाकर इतिश्री कर ली।

■ राजेन्द्र सिंह

गंगा भारतीय संस्कृति, सभ्यता, अस्मिता का प्रतीक है। भारत की दो–तिहाई खेती का प्राणाधार है। उसे राष्ट्रीय नदी घोषित करने की जरूरत क्या थी? पहली बात तो यह कि हमने गंगा के लिए सिर्फ राष्ट्रीय नदी का दर्जा नहीं मांगा था, हमने तो गंगा को राष्ट्रीय नदी प्रतीक घोषित करने की मांग की थी।

एक ऐसी ढांचागत व्यवस्था की मांग की थी, ताकि गंगा संरक्षण की जवाबदेही राज्य व केंद्र के बीच में न फंसे। हमने चाहा था कि गंगा संरक्षण के कार्य व निर्णय भिन्न विभागों के बीच तालमेल के अभाव व सरकारों की टालमटोल से मुक्त हों। उन्होंने सिर्फ राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया और एक प्राधिकरण बनाकर इतिश्री कर ली।

अफसोस यह भी है कि गंगा हमारे प्रधानमंत्री की प्राथमिकता नहीं बन सकी। जिस संवेदना, संजीदगी व तत्परता के साथ मनमोहन सिंह ने उसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया था, वह सब पिछले तीन साल के दौरान गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की कार्यप्रणाली व शैली, दोनों में ही कहीं दिखाई नहीं पड़ने से मेरा विश्वास आहत हुआ है।

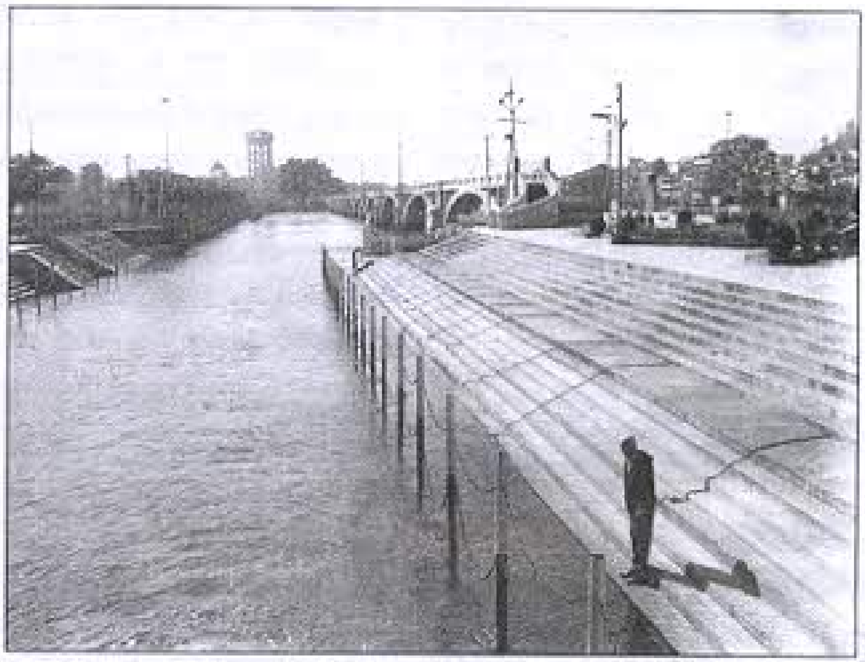

हमने सोचा था कि प्राधिकरण पूर्व में गंगा कार्ययोजना की गलतियों से सीखेगा। जो कुछ गंगा कार्ययोजना में हुआ, आज स्थिति उससे भिन्न क्या है? बैठकों में आए राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों का लक्ष्य भी सिर्फ 15 हजार करोड़ में से अधिकांश हथिया ले जाने से ज्यादा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। यदि सिर्फ घाट व सीढ़ियां बनाने, व एसटीपी के लिए पैसा बांटने के लिए ही परियोजनाओं की मंजूरी किसी प्राधिकरण का मुख्य कार्य हो जाए तो उसमें बने रहने का क्या औचित्य है?

गंगा प्राधिकरण का सदस्य बनना मैंने इसीलिए स्वीकार किया था कि वहां रहकर सरकार और समाज के बीच पुल बनाकर साझा जवाबदेही का कम से कम अहसास तो सुनिश्चित करा ही सकूंगा। उसके वैज्ञानिक पहलुओं व सामाजिक सरोकारों की अनदेखी न हो, ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए प्राधिकरण को सावधान कर सकूंगा।

गंगा को गंगा बनाने वाली छोटी–छोटी धाराओं, जलसंरचनाओं, वनस्पति, जीव, रेत व पत्थरों के संरक्षण को तवज्जो देने की बात उठा सकूंगा। गंगा पर आश्रित मल्लाहों, मछुआरों, तीर्थ

पंडा–पुरोहितों व खेतिहरों के अधिकारों की रक्षा हो सकेगी, किंतु मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि बतौर विशेषज्ञ सदस्य हमारे बार–बार कहने के बावजूद प्राधिकरण के अफसरों ने इन तमाम संजीदा मसलों को बैठकों के एजेंडे पर लाने की जरूरत ही नहीं समझी।

हम कहते रहे कि जब तक गंगा रक्षा के लिए कुछ सिद्धांतों को वैधानिक मान्यता नहीं प्रदान नहीं कर दी जाती, गंगा मास्टर प्लान–2020 बनकर मंजूर नहीं हो जाता, तब तक किसी परियोजना को पैसा न दिया जाए। सिद्धांत बनाया नहीं, काम तय कर लिए गए। कर्ज भी ले लिया। उन्होंने हमारी राय की उपेक्षा की।

हम कानून व नीति की मांग करते रहे, वे हमारी जानकारी व राय के बगैर 15 हजार करोड़ की परियोजनाओं को मंजूर करने के रास्ते बनाते रहे। इन परियोजनाओं में निर्माण, मशीनों की खरीददारी और ठेकेदारी के अलावा कुछ नहीं है।

हमने सोचा था कि प्राधिकरण पूर्व में गंगा कार्ययोजना की गलतियों से सीखेगा। जो कुछ गंगा कार्ययोजना में हुआ, आज स्थिति उससे भिन्न क्या है? बैठकों में आए राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों का लक्ष्य भी सिर्फ 15 हजार करोड़ में से अधिकांश हथिया ले जाने से ज्यादा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। यदि सिर्फ घाट व सीढ़ियां बनाने, व एसटीपी के लिए पैसा बांटने के लिए ही परियोजनाओं की मंजूरी किसी प्राधिकरण का मुख्य कार्य हो जाए तो उसमें बने रहने का क्या औचित्य है?

बतौर प्राधिकरण सदस्य हम सरकार से कुछ नहीं करा सके। करते भी तो कैसे? बतौर विशेषज्ञ जो हमारी भूमिका थी उसे सुनने को कोई राजी ही नहीं था। पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश कम से कम संवाद में तो रुचि दिखाते थे, नई पर्यावरण मंत्री ने तो वह रुचि दिखानी भी बंद कर दी है। पिछले तीन सालों में गंगा के मूल में बांध परियोजनाओं को रद कराने, गंगा दशहरा से गंगा सप्ताह मनाने का शासकीय निर्देश जारी कराने, मास्टर प्लान बनाने के लिए विदेशी कंपनी को दिया गया ठेका रद कराने से लेकर जो कुछ थोड़ा–बहुत काम हम करा सके, वह गंगा प्राधिकरण का सदस्य होने के नाते नहीं, गंगा लोकप्रेमी होने के नाते करा सके।

यह कैसे संभव है कि लोग गंगा की लड़ाई में मरते रहें और हम पद पर बने रहें? गंगा एक्सप्रेस वे के भूमि अधिग्रहण के विरोध में यूपी के रायबरेली व प्रतापगढ़ में कई लोगों की जान चली गई। मिर्जापुर के किसानों को उत्पीड़न सहना पड़ा। मंदाकिनी पर बांध व विस्फोट के विरोध में सुशीला भंडारी को जेल में ठूंस दिया गया। डॉलफिन रिजर्व के नाम पर बिहार के मछुआरों से उनका हक छीन लिया गया। शासन–प्रशासन ने स्वामी निगमानंद के प्राणों की आहूति लेकर ही दम लिया।

यह कैसे संभव है कि लोग गंगा की लड़ाई में मरते रहें और हम पद पर बने रहें? गंगा एक्सप्रेस वे के भूमि अधिग्रहण के विरोध में यूपी के रायबरेली व प्रतापगढ़ में कई लोगों की जान चली गई। मिर्जापुर के किसानों को उत्पीड़न सहना पड़ा। मंदाकिनी पर बांध व विस्फोट के विरोध में सुशीला भंडारी को जेल में ठूंस दिया गया। डॉलफिन रिजर्व के नाम पर बिहार के मछुआरों से उनका हक छीन लिया गया। शासन–प्रशासन ने स्वामी निगमानंद के प्राणों की आहूति लेकर ही दम लिया।

दो महीने से अधिक समय से अनशन पर बैठे स्वामी ज्ञानस्वरूप सानंद को उनकी मांग के प्रति आश्वस्त करना तो दूर, सरकार के किसी प्रतिनिधि ने उनसे बात तक करने की जरूरत नहीं समझी। यह निष्ठुरता की हद है। गंगा प्राधिकरण की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट होने के अलावा हमारे इस्तीफे का यह एक अन्य प्रमुख कारण है।

यदि सरकार चाहती है कि समाज व प्रकृति के प्रतिनिधि सरकार के साथ मिलकर गंगा कार्य कर सकें, तो गंगा प्राधिकरण के अध्यक्ष के तौर पर प्रधानमंत्री पहल करें। सबसे पहले प्रधानमंत्री खुद अथवा अपने प्रतिनिधि के रूप में गंगा प्राधिकरण के सदस्य केंद्रीय मंत्री में से किसी को जिम्मेदारी सौंपें कि वह स्वामी ज्ञानस्वरूप सानंद को उनकी मांग के प्रति आश्वस्त कर उनका जीवन बचाएं।

22 नवंबर, 2011 को जिस एजेंडे के साथ प्राधिकरण की आपात बैठक बुलाने का अनुरोध सात गंगा विशेषज्ञ सदस्यों ने किया था, उसे तत्काल बुलाया जाए। पूर्व की दो बैठकों में लिए गए सभी निर्णयों पर तत्काल कार्रवाई कर रिपोर्ट सदस्यों को सौंपी जाए। दरअसल, कुछ संशोधनों के साथ प्राधिकरण को पुनर्गठित किए जाने की जरूरत है। एक ऐसा सशक्त कानून व कार्य ढांचा बनाने की मांग हम पहले दिन से कर रहे हैं ताकि गंगा की अविरलता और निर्मलता सुनिश्चित हो सके। ❑

देख रही हो गंगा माई, अब हम हवा में उड़ रहे हैं

जब पहली बार हवाई जहाज से पटना गया तो शहर के ऊपर से निकलते हुए जहाज अचानक गंगा के ऊपर से मुड़ने लगा। खिड़की से झांककर देखा तो गंगा बीमार लग रही थी। उसकी गोद से रेत के गाद निकल आए थे। ऐसा लगा कि किसी ने गंगा की लाद को चीर दिया है। प्रणाम तब भी किया। हाथ तो नहीं जोड़ा लेकिन मन ही मन। देख रही हो न गंगा माई, अब हम हवा में उड़ रहे हैं। बहुत दुख हुआ अपनी गंगा को देखकर।

■ रवीश कुमार

पहलेजा घाट से बच्चा बाबू के जहाज से एलसीटी घाट तक की यात्रा में एक ही कसक होती थी। उफनती लहरों के बीच उबला अंडा बाबूजी खिला दें। उसका पीला हिस्सा और ऊपर काली मिर्च की कतरनें। धोती कुर्ता में पितृपुरुष जब पूछ लेते थे कि खाना है तो लगता था कि गंगा की तरह कितनी ममता है इनमें। गांव से पटना की बीच गंगा जरूर होती थी। उसके बाद स्कूल के रास्ते में कई वर्षों तक समानांतर बहती रही। ठीक से याद है कि जमाने तक गांव से लेदी (गाय का चारा) और हम लोगों के खाने का अनाज नाव पर लाद कर आता था। गंगा ले आती थी। जब नाव आती थी तो घर मलाहों से भर जाता था। मछली का स्वाद बदल जाता था। उनकी चमकती बाजुओं की बलिष्ठता आकर्षित करती थी। लगता था कि कितनी शक्ति है इन मलाहों में। सिक्स पैक वाले खानों से बहुत पहले हमने स्वाभाविक बलिष्ठता अपने गांव के मलाहों में देखी थी। मालूम नहीं था कि सड़क और मोटर क्रांति नदियों से सामाजिक रिश्ते को खत्म कर देगी। और फिर एक दिन नदियां भी खत्म होने लगेंगी।

फिर वो वक्त आया जब पटना एशिया से लेकर विश्व तक में प्रसिद्ध हो गया। गंगा नदी पर पुल बन गया। गांधी सेतु। हम गंगा के ऊपर से उड़ने लगे। मोतिहारी पटना की दूरी कई घंटों की जगह पांच घंटे में सिमट गई। अब उबले अंडे का रोमांच चला गया था। वो विशिष्ट नहीं रहा। पटना की सड़कों पर सर्दी में मिलने लगा था। बाबूजी कहते थे कि साहब लोगों का नाश्ता होता है। सीखो खाना। लेकिन बाबूजी अब मोतिहारी पटना के बीच बने लाइन होटलों पर रूकने लगे। मीट और भात। सिरुआ और पीस की बात होने लगी। हाजीपुर रूककर बस से हाथ निकालकर मालभोग केला। दूर कहीं गंगा छूटती नजर आने लगती थी। उसकी ठंडी हवा याद दिलाती रहती थी कि हमारी धारा से न सही, धारा के ऊपर से तो गुजरने लगे हो। फिर भी हाईवे पर ट्रकों के कपार पर गंगा तेरा पानी अमृत लिखा देखता तो कुछ हो जाता। लगता कि गंगा है तो, भले ही गंगा हमारे रास्ते में नहीं है। अब तो गंगा तेरा पानी अमृत भी सड़क साहित्य से गायब हो चुका है। हमलोगों ने गांधी सेतु को रास्ता बना लिया था। गंगा छूट गई थी। दिल्ली आने के बाद बनारस के पास गंगा दिखने लगी। तेजी से गुजर जाती। कई सालों तक दिल्ली पटना के रास्ते में खिड़की पर बैठा बनारस का इंतजार करता रहता था। गंगा को प्रणाम करने के लिए। आज भी करता हूं। किसी अंध श्रद्धा से नहीं। गहरे रिश्ते के कारण। गंगा को देखना और देखते रहना आज भी जीवन के सर्वोत्तम रोमांच में से एक है। धीरे धीरे पटना जाना कम होने लगा। गंगा दिखनी कम हो गई।

जब पहली बार हवाई जहाज से पटना गया तो शहर के ऊपर से निकलते हुए जहाज अचानक गंगा के ऊपर से मुड़ने लगा। खिड़की से झांककर देखा तो गंगा बीमार लग रही थी। उसकी गोद से रेत के गाद निकल आए थे। ऐसा लगा कि किसी ने गंगा की लाद को चीर दिया है। प्रणाम तब भी किया। हाथ तो नहीं जोड़ा लेकिन मन ही मन। देख रही हो न गंगा। अब हम हवा में उड़ रहे हैं। बहुत दुख हुआ अपनी गंगा को देखकर। गांधी सेतु भी गंगा की तरह जर्जर हो चुका है। गंगा को हमने खूब देखा है। चौड़े पाट। बेखौफ लहरें। नावें। कभी कभी मोहल्ले के दोस्तों के साथ बांस घाट में नहाना। वो भाव कभी नहीं उमड़ा जो पटना में गंगा को देखकर होता था। हरिद्वार और बनारस में गंगा अल्बम की तस्वीर लगती थी। अभी तक मैंने नदियों के मसले को लेकर किसी आंदोलन के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा था। बस एक रिश्ता था जो स्मृतियों में धंसा हुआ है।

गंगा को लेकर गाने यूट्यूब पर खूब सुनता रहा हूं। गंगा मइया, मइया, हो गंगा मइया, गंगा मइया में जब तक कि पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे। क्यों रो देता हूं मालूम नहीं। गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जाए। याद तो नहीं जब गंगा मइया तोरे पियरे चढ़इबो देखी थी तो दिल खूब मचला था। इस गाने में बनारस की गंगा की जवानी देखियेगा। क्या लहरें हैं। क्या मस्ती है। कितनी नावें एक साथ चल रही हैं। हे गंगा मइया तोहे पियरी चढ़इबो, सइयां से कर दे मिलनवा हाय राम। मालूम ही नहीं था गंगा महबूब के आने का रास्ता भी है। उसे मिलाने का जरिया भी है। इस गाने में गंगा में जो नावों की भीड़ है वो बताती है कि गंगा पवित्र पावनी से ज्यादा नदी मार्ग थी। हमारे आने जाने का जरिया। पॉल रॉबसन तुम्हारी मिसिसिपी को हमने नहीं देखा है। पढ़ा था कभी किताबों में। समझ सकता हूं एक नदी का बुढ़ाना। अविनाश के फेसबुक वॉल पर तुम्हारे जन्मदिन की बात देखी। बूढ़े नदी को कुछ तो मालूम ही है। गंगा को भी कुछ क्या सब मालूम है। पर उसे मालूम ही नहीं कि वो बहती है क्यों? ❑

रामसेतु को बचाइये

तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने केन्द्र से मांग की है कि वह रामसेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करें। यह मांग सिर्फ जयललिता की ही नहीं है। देश की बहुसंख्यक जनता भी यही चाहती है। रामसेतु समुद्रम परियोजना का मामला सुप्रीम कोर्ट में है और उसने भी केन्द्र से सवाल किया है कि क्या रामसेतु राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जा सकता है या नहीं। इस पर वह अपना स्पष्ट रूख पेश करे। द्रमुक के अध्यक्ष एम करूणानिधि और उनकी पार्टी को छोड़कर कोई नहीं यह चाहता है कि रामसेतु को तोड़कर रामसेतु समुद्रम परियोजना पूरी की जाए।

■ निरंकार सिंह

तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने केन्द्र से मांग की है कि वह रामसेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करें। यह मांग सिर्फ जयललिता की ही नहीं है। देश की बहुसंख्यक जनता भी यही चाहती है। रामसेतु समुद्रम परियोजना का मामला सुप्रीम कोर्ट में है और उसने भी केन्द्र से सवाल किया है कि क्या रामसेतु राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जा सकता है या नहीं। इस पर वह अपना स्पष्ट रूख पेश करे। द्रमुक के अध्यक्ष एम करूणानिधि और उनकी पार्टी को छोड़कर कोई नहीं यह चाहता है कि रामसेतु को तोड़कर रामसेतु समुद्रम परियोजना पूरी की जाए।

भारत के पास विश्व की महानतम धरोहर के रूप में मानव निर्मित रामसेतु है। इसे इसलिए भी राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया ही जाना चाहिए क्योंकि देश के करोड़ों लोगों की आस्था श्रीराम और रामसेतु में है। लोकतंत्र बहुमत से चलता है और जब बहुसंख्यक हिन्दू समाज की रामसेतु में आस्था है तो उसकी उपेक्षा कैसे की जा सकती है। रामायण में वर्णित रामेश्वर की स्थापना वर्तमान इतिहास से भी प्रमाणित होती है। सहस्त्राब्दियों से भारत के कोने–कोने से लोग रामेश्वर का दर्शन करने जाते हैं। पुराणों में इन बातों का विशद वर्णन है। कूर्मपुराण पूर्वभाग के इक्कीसवें अध्याय में आये 49 से 51वें श्लोकों से रामेश्वर की महत्ता तथा प्राचीनता स्पष्ट होती है।

इसी प्रकार के अन्य वचन स्कन्दपुराण तथा अन्यान्य पुराणों में भी मिलते हैं। इन वचनों तथा मान्य ग्रन्थों के प्रमाणों के अतिरिक्त रामेश्वर नाम ही रामेश्वर की मूर्ति और मन्दिर का भगवान राम के साथ असाधारण सम्बन्ध स्थापित करता है। अतः

भारत के पास विश्व की महानतम धरोहर के रूप में मानव निर्मित रामसेतु है। इसे इसलिए भी राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया ही जाना चाहिए क्योंकि देश के करोड़ों लोगों की आस्था श्रीराम और रामसेतु में है। लोकतंत्र बहुमत से चलता है और जब बहुसंख्यक हिन्दू समाज की रामसेतु में आस्था है तो उसकी उपेक्षा कैसे की जा सकती है। रामायण में वर्णित रामेश्वर की स्थापना वर्तमान इतिहास से भी प्रमाणित होती है।

सेतुबन्ध रामेश्वर की घटना वाल्मीकि रामायण द्वारा वर्णित रामेश्वर से भिन्न वस्तु नहीं हो सकती। सेतु निर्माण की घटना मात्र कल्पना नहीं है। वाल्मीकि रामायण में सेतु निर्माण की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन किया गया है। उसका प्रारंभ, समाप्ति और नाप जोख सब पर इस रामायण में प्रकाश डाला गया है। वाल्मीकि रामायण के युद्ध काण्ड के 22 वें सर्ग के 50 से 72 वें श्लोक तक प्रतिदिन कितना निर्माण हुआ, कितने

सन् 1803 में प्रकाशित 'ग्लोरी आफ मद्रास प्रेसीडेंसी' के अनुसार इस सेतु से लोग 1480 तक भारत और लंका से आते–जाते थे। इसका अर्थ यह हुआ कि सेतु भारतीय प्रायद्वीप को श्रीलंका से जोड़ता था। सन् 1480 में आये भयानक तूफान से सेतु की ऊपरी सतह पर 6 फुट से 30 फुट तक पानी आ जाने से सम्पर्क टूट गया। यह बात वैज्ञानिक शोध पत्रों से भी स्पष्ट होती है।

दिनों में सेतु बनकर तैयार हुआ इसका ब्यौरेवार वर्णन किया गया है। पूर्ण सेतु का निर्माण पाँच दिनों में हुआ था। प्रथम दिन 14 योजन, दूसरे दिन 20, तीसरे दिन 21, चौथे दिन 22 एवं पांचवे दिन 10 योजन बना। आधुनिक युग में विभिन्न देशों में निर्मित अत्यन्त विशाल सेतुओं की उपस्थिति उक्त सेतुबन्धन की घटना को वास्तविक मानने को बाध्य करती है। किसी भी निर्माण के सदियों गुजरने के बाद केवल उसका विकृत रूप अर्थात् भग्नावशेष ही रह जाते हैं। फिर रामसेतु को बने तो लाखों वर्ष हो गये हैं। ऐसी दशा में वह अपने स्वरूप में कैसे रह सकता है।

सन् 1803 में प्रकाशित 'ग्लोरी आफ मद्रास प्रेसीडेंसी' के अनुसार इस सेतु से लोग 1480 तक भारत और लंका से आते–जाते थे। इसका अर्थ यह हुआ कि सेतु भारतीय प्रायद्वीप को श्रीलंका से जोड़ता था। सन् 1480 में आये भयानक तूफान से सेतु की ऊपरी सतह पर 6 फुट से 30 फुट तक पानी आ जाने से सम्पर्क टूट गया। यह बात वैज्ञानिक शोध पत्रों से भी स्पष्ट होती है।

महर्षि वाल्मीकि ने भगवान राम के समुद्र तक पहुँचने के विभिन्न मार्गों का विशद वर्णन किया है। आज भी उन्हीं मार्गों से दक्षिण भारत की तीर्थयात्रा होती है। किष्किन्धा में बाली को मारकर राम ने चौमासा किया था। यह किष्किन्धा दक्षिण भारत में आज भी किष्किन्धा नाम से ही प्रसिद्ध है। नासिक का सम्बन्ध रामायण की महत्वपूर्ण घटना शूर्पणखा के नासिका छेदन से है। पंचवटी भी वहीं है। रामायण से भी दोनों स्थानों का

अंतरिक्ष विभाग की हैदराबाद स्थित नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेन्सी द्वारा प्रकाशित पुस्तक इमेजेज इंडिया के मुताबिक उपग्रह में लिये गये चित्र इस बात के साक्षी हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच एक प्राचीन पुल स्थित है। उसमें भी कहा गया है कि पुल की उत्पत्ति एक रहस्य है। इसके स्टनिंग स्ट्रक्चर अध्याय के अनुसार पुल का ढांचा इस बात का पर्याप्त सबूत है कि रामसेतु मानव निर्मित है।

पास–पास होना प्रमाणित होता है।

आधुनिक काल में भी पंचवटी और नासिक एक ही स्थान पर हैं। इन स्थानों का वाल्मीकि रामायण के वर्णन से साहचर्य सम्बन्ध प्रतीत होता है। महाकवि ने रामायण में लगभग दो सौ साठ स्थानों का वर्णन किया है। इनमें से अधिकांश स्थान आज भी दक्षिण भारत में ही हैं। गोदावरी, कृष्णा, वरदा आदि नदियां आन्ध्र, चोल, पाण्डय, केरल आदि स्थान दक्षिण भारत में ज्यों के त्यों विद्यमान हैं। यदि रामायण में वर्णित भौगोलिक स्थान पर पर्वत, नदी, तीर्थ आदि आज भी यथा स्थान हैं तो उनके द्वारा वर्णित एवं उनसे जुड़ी कृतियां किस प्रकार झूठी हो सकती हैं। अंतरिक्ष विभाग की हैदराबाद स्थित नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेन्सी द्वारा प्रकाशित पुस्तक इमेजेज इंडिया के मुताबिक उपग्रह में लिये गये चित्र इस बात के साक्षी हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच एक प्राचीन पुल स्थित है।

उसमें भी कहा गया है कि पुल की उत्पत्ति एक रहस्य है। इसके स्टनिंग स्ट्रक्चर अध्याय के अनुसार पुल का ढांचा इस बात का पर्याप्त सबूत है कि रामसेतु मानव निर्मित है। एक सरकारी एजेंसी ने भी स्वीकार किया है कि रामसेतु मानव निर्मित है और प्रागैतिहासिक यानी रामायणकालीन है। उधर श्रीलंका के वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं ने भी यह माना है कि रामसेतु सुनामी लहरों की सुरक्षा की दृष्टि से अत्यधिक उपयोगी है। इसको मिटाना हानिकारक होगा। उनके इस कथन में भी सच्चाई है कि पूर्व में आई सुनामी लहरों से इस सेतु के कारण कोई नुकसान नहीं हो पाया। यदि धार्मिक दृष्टि से न सही तो वैज्ञानिक दृष्टि से सही, इस रामसेतु को ध्वस्त करना ही लाभदायक और उपयुक्त है। इसलिए रामसेतु समुद्रम परियोजना के लिए वैकल्पिक उपाय किये जाने चाहिए। यूपीए सरकार को ऐसे मामलों से बचना चाहिए जिसके साम्प्रदायिक सद्भाव को चोट पहुँचती हो। भगवान राम और उनसे जुड़े स्थलों से छेड़छाड़ करना सरकार और देश दोनों के हित में नहीं है।

युगों–युगों से राम भारतीय जनमानस के आराध्य रहे हैं। हिन्दू उन्हें परब्रह्म विष्णु का अवतार मानते हैं। मनुष्य के जीवन में जो भी श्रेष्ठ और सुन्दर है उसकी उत्पत्ति तो राम चरित्र से ही बतायी जाती है। दुनिया में कई प्राचीन सभ्यताओं का जन्म हुआ जो समय के साथ इतिहास के गर्त में खो गयी, किन्तु युगों–युगों से इस देश में राम का गौरव आज भी कायम है। राम की कथा और उनका चरित्र अमर है क्योंकि वे कालजयी हैं।

यदि भारत में आज कोई ईमानदारी, अतिथि सत्कार, सतीत्व, परोपकार, मूक पशुओं के प्रति दया भाव, पाप से घृणा तथा भलाई की भावना है तो वह जनमानस में रामचरित्र के प्रति आस्था के ही कारण है। पुरानी आस्था तथा संस्कृति केवल हिन्दुओं या भारतीयों के लिए नहीं बल्कि समूचे संसार के लिए सार्थक है। भारत की धार्मिक स्वतंत्रता तथा सहनशीलता की परम्परा अद्वितीय है।

इस परम्परा का जन्म उस चेतना के फलस्वरूप हुआ था जिसमें सत्य पर किसी जाति या सम्प्रदाय विशेष का अधिकार नहीं होता। ऋग्वेद का यह वाक्य विश्व प्रसिद्ध है –'आदर्श विचारों को हर दिशा से आने दो।' पर वर्तमान युग आध्यात्मिक अज्ञान एवं आत्मा की निर्धनता का युग है। जब मनुष्य अपनी आत्मा को झूठे भौतिक वैभव से धोखा देकर आत्मा के कवित्वमय बोध को नष्ट सकता है तो हमें यह यह स्मरण करना आवश्यक हो जाता है कि सभ्यता आत्मा की ही देन है। भौतिक उन्नति को आत्मा की उन्नति नहीं समझना चाहिए। जब टेक्नालॉजी नैतिक उत्थान से श्रेष्ठ हो जाती है तो सभ्यता स्थिर रहने के स्थान पर लुप्तप्राय होने लगती है।

हमारे पुराने ऋषियों ने किसी राज्य की महानता उसके आकार तथा धन–सम्पत्ति से नहीं बल्कि उस राज्य में नागरिकों की भलाई के लिए होने वाले लोक प्रशासन में न्याय तथा न्याय संगत कार्यों के आधार पर आंकी थी। उनकी अमर शिक्षा कि मनुष्य का वास्तविक विकास भौतिक तथा शारीरिक मानवों के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। बलिदान सफलता से अधिक महत्वपूर्ण तथा त्याग सफलता का सर्वोच्च मापदण्ड था।

किसी नागरिक का समाज में मान–सम्मान धन सम्पत्ति या सत्ता के आधार पर नहीं बल्कि ज्ञान के स्तर, गुण तथा चरित्र के आधार पर होता था। हमारे ऋषियों ने राम के जीवन चरित्र को आदर्श चरित्र के रूप में निरूपित किया है। इसलिए किसी भी प्रकार से श्रीराम और रामसेतु की अवहेलना निरादर समाजद्रोही ही नहीं बल्कि राष्ट्रद्रोही कहा जायेगा। ❑

श्रद्धेय दत्तोपंत जी का अलौकिक सान्निध्य

मैंने पूछा – आप तो संघ के प्रारंभ से संघकार्य देख रहे है और आज तक देख रहे हैं आपको क्या लगता है? जैसा आप लोगों ने सोचा वैसा ही, संघ चल रहा है? और क्या हम अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे? श्रद्धेय दत्तोपंत जी ने कहा "इसमें किंचित भी संदेह की आवश्यकता नहीं है। जैसे संघ की हमारी कल्पना थी; योजना थी; ठीक वैसा ही संघ चल रहा है और बन रहा है। फिर कहा कि संघ अपना लक्ष्य निश्चित प्राप्त करेगा। इसका कारण केवल आपका योगदान मात्र नहीं है, यह ईश्वरीय इच्छा है जो सदैव पूरी होती है।

■ डॉ. रणजीत सिंह

बात 1990 की है। मुझे पहली बार श्रद्धेय दत्तोपंत जी के दर्शन किये। 1992 में, तृतीय वर्ष, संघ शिक्षा वर्ग नागपुर में दो दिन धारा – प्रवाह बौद्धिक वर्ग सुने। एक दिन, रात्रि भोजन पश्चात अनौपचारिक सत्र में, सुनने का अवसर मिला और तृतीय वर्ष के समारोह में सामान्यतया परम पूज्य सरसंघचालक जी का उद्बोद्धन होता है। परन्तु, परम पूज्य बाला साहब का स्वास्थ्य अत्यन्त शिथिल होने के कारण, समारोप समारोह में, प.पू. सर संघ चालक जी के सानिध्य में, मुख्य वक्ता के रूप में श्रद्धेय दत्तोपंत जी का उद्बोद्धन रखा गया था।

सन 1998 में भारतीय मजदूर संघ का प्रदेश अधिवेशन, आबूरोड राजस्थान में आयोजित होने जा रहा था। श्रद्धेय दत्तोपंत जी अधिवेशन में पूरा समय रहने वाले है, यह समाचार हम सभी कार्यकर्ताओं को था।

मैं उस समय आबूरोड में कार्यरत था और भारतीय मजदूर संघ के मित्रों के साथ, सतत संपर्क में था। जैसे–जैसे अधिवेशन की तिथियां निकट आ रही थी, अनेक बार मन में, ऐसा मोह जाग्रत होता कि श्रद्धेय दत्तोपंत जी की आवास व्यवस्था मेरे घर पर रखने का आग्रह किया जाए, परन्तु दूसरे क्षण सोचता कि,

ऐसा कहना ठीक नहीं होगा, आखिर, अनेक अन्य कार्यकर्ता भी ऐसा चाहते होगें। अंततोगत्वा यह समाचार भी प्राप्त हो गये कि सभी व्यवस्थाएं तय हो गई है और श्रद्धेय दत्तोपंत जी किसी अथितिग्रह में रूकेगें।

अधिवेशन से दो दिन पूर्व, प्रातः 8–9 बजे, भारतीय मजदूर संघ, आबूरोड इकाई के महामंत्री श्री सचिन जी, एक, वरिष्ठ सज्जन के साथ घर आये। सचिन जी ने परिचय करवाया कि आप भारतीय मजदूर संघ राजस्थान के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री श्याम सुन्दर शर्मा है और एक व्यवस्था में बदलाव चाहते है कि, श्रद्धेय दत्तोपंत जी अथितिग्रह में नहीं रूकेगें। उनकी व्यवस्था किसी कार्यकर्ता के घर करनी होगी।

आगे की बात श्री श्याम सुन्दर जी, ने स्पष्ट की "हम आपको एक कष्ट देने आये है, अगर आप कि अनुमति हो, तो श्रद्धेय दत्तोपंत जी की आवास की व्यवस्था आपके घर करना चाहते है।"

मैंने उस दिन स्वीकार कर लिया कि, भगवान सुनते है, और अवश्य सुनते है।

10 सितम्बर 1998 को श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगडी, आबूरोड पहुंचे। हम सभी रेलवे स्टेशन से घर तक ले आये। चार दिन तक अखिल भारतीय अधिकारी का आवास रहेगा, यह सोच कर, सारा परिवार, आनन्द के साथ, तनाव में भी था। श्रद्धेय दत्तोपंत जी ने घर में प्रवेश करते ही, सबका परिचय पूछा, फिर पूरे घर का निरिक्षण किया, क्या – क्या, कहां – कहां है। और आधे घंटे में, खाना–पीना, सोना–रहना आदि सारी व्यवस्थाओं के बारे में स्पष्ट मार्गदर्शन

10 सितम्बर 1998 को श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगडी, आबूरोड पहुंचे। हम सभी रेलवे स्टेशन से घर तक ले आये। चार दिन तक अखिल भारतीय अधिकारी का आवास रहेगा, यह सोच कर, सारा परिवार, आनन्द के साथ, तनाव में भी था। श्रद्धेय दत्तोपंत जी ने घर में प्रवेश करते ही, सबका परिचय पूछा, फिर पूरे घर का निरीक्षण किया, क्या – क्या? कहां – कहां है।

करके, सभी को हल्का कर दिया अब तनाव नहीं था, केवल अलौकिक सानिध्य का आनन्द था। और हम सब उस आनन्द से सराबोर थे।

श्रद्धेय दत्तोपंत जी का स्वास्थ्य एकदम अच्छा था। चिकित्सक होने के कारण, मैंने पूछा आपका स्वास्थ्य कैसा रहता है। दत्तोपंत जी ने कहा "ईश्वर की कृपा से सब ठीक है, आयु के कारण कुछ कम सुनाई देता है। उसके लिए मशीन का उपयोग करना पड़ता हैं।"

रात्रि भोजन के पश्चात मुझे कहा कि, सवेरे कितने बजे उठते हो, मैंने कहा "पांच बजे" तो बोले, अच्छा है, सवेरे मुझे, जगाने की आवश्यकता नहीं हैं, जब नींद खुल जाएगी तब, आपको बता दूंगा। फिर बोले "आजकल ऐसा चल रहा है, कि जब तक नींद नहीं आती, तब तक पढ़ना–लिखना करता हूँ। जब नींद आती है, तभी सोता हूँ। और जब नींद खुल जाती है, तब उठता हूं। इसलिए आप आराम से सो जाइए।" ऐसा कहकर मेरी पुस्तकों में से, 2–4 पुस्तकें निकाली और पढ़ने बैठ गये।

सुबह हम सब, उनके उठने का, बेसब्री से इन्तजार करने लगे, इंतजार करने, वालों में मेरी, दादीजी, जो उस समय 90 वर्ष के थे। मेरा छोटा पुत्र जो तीन वर्ष का था, शामिल थे, कैसा था, उस सर्वस्पर्शी सानिध्य का आकर्षण?

प्रातः स्नान – अल्पाहार आदि से निवृत होकर वे मेरा पुस्तक संग्रह देख रहे थे, एक–एक पुस्तक के बारे में पूछते, इसको पढ़ा क्या? फिर उसके बारे में कुछ, टिप्पणी करते , इसी क्रम में श्री अरविन्द की पुस्तक "भारत का पुनर्जन्म" को हाथ में लिया और पूछा, इसको पढ़ा क्या? मैंने हाँ में गर्दन हिलाई, बोले, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। और मैंने मोका देखकर पूछा 'हम स्वदेशी जागरण मंच के कार्यक्रमों में महात्मा गांधी और श्रीअरविन्द, दोनों के चित्र लगाते हैं और इस पुस्तक में श्रीअरविन्द ने महात्मा गांधी की कठोर आलोचना की है?

उन्होने कहा "आप ठीक कह रहे है" लेकिन बड़े लोगों की बड़ी बाते है। फिर पुस्तक हाथ में लेकर बैठ गये, और बोले कि "हमारे साथ भी एक बार ऐसा ही हुआ। यह कोई 1960 के आस–पास की बात है, परम पूजनीय गुरुजी का भोपाल प्रवास था। हमारे ध्यान में था कि परम पूजनीय गुरूजी, कई विषयों पर महात्मा गांधी के कुछ विचारों का कठोर प्रतिवाद करते थे। गुरूजी के प्रवास के से,कुछ दिन पूर्व किसी कार्यक्रम में, मैंने, महात्मा गांधी जी के कुछ विचारों की आलोचना की थी, वह समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हो गई थी।

भोपाल प्रवास में, परम पूजनीय गुरूजी के साथ शाम के समय भेंट हुई । चाय का समय था, परम पूज्य गुरूजी ने, क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, सब हाल पूछा फिर बोले " आजकल तुम्हारे बड़े–बड़े वक्तव्य छपते है" मैं प्रसन्न हो रहा था, सोच रहा था कि शाबासी दे रहे है' परन्तु एक क्षण में ही गुरुजी अत्यन्त ही गंभीर हो गये, फिर बोले "संघ के सर संघ चालक का दायित्व होने के कारण, हिन्दु समाज के व्यापक हित–अहित के संबंध में, मुझे अपने विचार समाज के सामने रखने होते है अन्यथा आने वाले सौ जन्मों तक महात्मा गांधी हमारे लिए आदरणीय रहेंगें।"

मुझे अपनी नादानी समझ में आ गई। महर्षि अरविन्द को महात्मा गांधी की आलोचना करने का अधिकार है, वे अधिकारी पुरुष है, हमारे लिए दोनो पूजनीय है।

भोपाल प्रवास में, परम पूजनीय गुरूजी के साथ शाम के समय भेंट हुई । चाय का समय था, परम पूज्य गुरूजी ने, क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, सब हाल पूछा फिर बोले "आजकल तुम्हारे बड़े–बड़े वक्तव्य छपते है" मैं प्रसन्न हो रहा था, सोच रहा था कि शाबाशी दे रहे है' परन्तु एक क्षण में ही गुरूजी अत्यंत ही गंभीर हो गये, फिर बोले "संघ के सरसंघचालक का दायित्व होने के कारण, हिन्दु समाज के व्यापक हित–अहित के संबंध में, मुझे अपने विचार समाज के सामने रखने होते हैं।

दत्तोपंत जी ने कहा "ईश्वर की कृपा से सब ठीक है, आयु के कारण कुछ कम सुनाई देता है। उसके लिए मशीन का उपयोग करना पड़ता है।" रात्रि भोजन के पश्चात मुझे कहा कि सवेरे कितने बजे उठते हो, मैंने कहा 'पांच बजे' तो बोले, अच्छा है, सवेरे मुझे, जगाने की आवश्यकता नहीं हैं, जब नींद खुल जाएगी तब आपको बता दूंगा।

मेरे मामाजी कहते थे, कि जो लोग कहते है कि हम कई दिनों से विचार कर रहे है, वे वास्तव में विचार नहीं करते, जप करते रहते है, "ऐसा करें, नहीं नहीं वैसा करे, ऐसा करें, नहीं नहीं वैसा करे" ऐसा जप करते है, अब यह जप तो जीवन भर चल सकता है, लेकिन विचार करने की क्षमता सभी के पास सीमित समय की होती है, यह अनुभव सिद्ध बात है।

विचार करते है या जप करते है?

दोपहर को कुछ समय मिला तो मैंने पूछा, कि, "इतनी सारी व्यस्तताओं, समस्याओं, के बावजूद आप इतना शान्त कैसे रहते है?

दत्तोपंत जी बोले "समस्याएं तो रहती ही है" परन्तु मेरा ऐसा मानना है कि प्रत्येक मनुष्य की विचार करने की क्षमता सीमित होती हैं। हर एक मनुष्य किसी एक विषय पर एक निश्चित समय तक विचार कर सकता है। यह ठीक है कि, विचार करने की समय सीमा हर एक व्यक्ति की अलग–अलग हो सकती है। परन्तु विचार करने की शक्ति सीमित समय तक होती है, माने की किसी की 30 मिनट है तो किसी की 40 मिनट हो सकती है। इससे अधिक विचार करने की क्षमता, मनुष्य में नहीं होती है, यह ध्यान में लेने की बात है।

मेरा विचार करने का ढंग ऐसा है कि उपस्थित, सारी समस्याओं और प्रश्नों को पहले, तीन भागों में बांट लेता हूँ। कुछ सवाल या समस्याएं ऐसी होती है, जिनका फिलहाल, कोई समाधान नहीं है, या फिर समाधान ही नहीं हैं, ऐसी समस्याओं का छोड़ देता है। दूसरी वे, जिनके समाधान में कुछ समय आवश्यक है, अभी उचित समय नहीं है, उनको भी रहने देता हूं। और तीसरी, जिनका तत्काल निदान संभव है, आज केवल उनके संबंध में विचार करता हूँ। और विचार करने की पद्धती ऐसी रहती है कि प्रत्येक समस्या के लिए विचार करने के लिए समय तय कर लेता हूँ, जैसे 10 से 11 बजे तक का समय तय कर लिया, तो 10 से 11 बजे के बीच विचार करके निर्णय स्थिर करते है, जैसे ही 11 बज गये, तब तक जो भी समाधान निश्चित हो गया उसको स्वीकार कर लेते है। और फिर उस पर निरर्थक पुनर्विचार नहीं करते।

मेरे मामाजी कहते थे, कि जो लोग कहते है कि, हम कई दिनों से विचार कर रहे है, वे वास्तव में विचार नहीं करते, जप करते रहते है, "ऐसा करें , नहीं नहीं वैसा करे, ऐसा करें, नहीं नहीं वैसा करे" ऐसा जप करते है, अब यह जप तो जीवन भर चल सकता है, लेकिन विचार करने की क्षमता सभी के पास सीमित समय की होती है, यह अनुभव सिद्ध बात है।

कान भरने की कला

मैंने सवाल किया कि, अनेक बार, एक ही ध्येय के लिए, अगाध श्रद्धा रखने वाले कार्यकर्ताओं के बीच भी मन भेद क्यों खड़े हो जाते है?

श्रद्धेय दत्तोपंत जी बोले "ऐसा है, कि पिछले 10–15 वर्षों में, यह समस्या ज्यादा दिखने लगी है, इसका कारण है, एक तो हमारे अधिकारी कार्यकर्ता है वो, जरा कान के कच्चे हो गये है" कान के कच्चे माने क्या? उदाहरण के लिए, मेरा कहीं बौद्धिक वर्ग हुआ। एक दो माह बाद वहाँ, से कोई कार्यकर्ता दिल्ली आता है, मुझसे मिलता है, कहता है, दत्तोपंत जी, इस बार आपका बौद्धिक वर्ग बहुत अच्छा हुआ। लोग कह रहे थे कि, ऐसा बौद्धिक वर्ग उन्होंने जीवन में नहीं सुना "मुझे जरा अच्छा लगता है, अरे! यह मेरी असली कदरदान है, मैं बोलता हूँ, अरे क्या कहा, आओ, जरा पास में आकर कहो, आओ पास में आ जाओ, फिर से कहो।"

उसको लगता है, लोहा गरम है, पास में आकर बोलता है, सब लोग बड़ी तरीफ कर रहे थे, परन्तु...... और रूक जाता है, मुझे बड़ा अटपटा लगता है, कहता हूँ क्या? परन्तु, बोलो ना , परन्तु क्या? वह बोलता है "रहने दो ठेंगडी जी, कोयला तो काला ही रहेगा, मेरे मुँह से क्यों कहलवाते

उसको लगता है, लोहा गरम है, पास में आकर बोलता है, सब लोग बड़ी तरीफ कर रहे थे, परन्तु....... और रूक जाता है, मुझे बड़ा अटपटा लगता है, कहता हूँ क्या? परन्तु, बोलो ना , परन्तु क्या? वह बोलता है "रहने दो ठेंगडी जी , कोयला तो काला ही रहेगा, मेरे मुँह से क्यों कहलवाते हो? अब हमारी उत्सुकता और बढ़ जाती है, "बताइएना, किसने क्या कहा?

हो?

अब हमारी उत्सुकता और बढ़ जाती है, "बताइएना, किसने क्या कहा? वह बोलता है, "अरे अपने, संकटा जी है ना...

मैं फिर पूछता हूँ बताइये ना, संकटा जी ने क्या कहा? वह फिर बोलता है "रहने दो ठेंगडी जी, मेरे मुँह से क्यों कहलवाते हो?"

अब देखिये! ऐसी बात है, अनेक बार क्या होता कि हम ही आवेश में आकर, कुछ बोल देते है, अच्छा उन्होंने ऐसा कहा। अरे मैं जानता हूँ, वह क्या है आदि – आदि या नहीं बोलते है तो, भी मन में गांठ बांध लेते है।

आश्चर्य की बात है, हमें समझ में ही नहीं आता कि वह नाम लेता जा रहा है, फिर कहता है, मेरे मुँह से क्यों कहलवाते हो, स्वंय कह रहा है। ऐसी परिस्थिति में दो ही उपाय है। पहला तो यह कि अपने सहयोगियों पर अटूट भरोसा रहे; अविचल भरोसा रहे। कोई कितना भी कहे तो हमारा अपने सहयोगियों के लिए अडिग विश्वास होगा तो हम एक मिनट में, झटक देंगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता।

दूसरा उपाय है – धैर्यपूर्वक पूरी बात सुनकर, बिना किसी टीका टिप्पणी के; अपना साइकिल उठाओ और बिना समय खराब किये अपने सहयोगी से मिलने चले जाओ। सारी बात साफ–साफ कर लो, सारा समाधान हो जाएगा।

अखंड सावधान रहना होगा, अखंड सावधान रहेंगे तो कान भरने की कला हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी।

कार्यक्रम की कार्यपद्धति

सायं सार्वजनिक सभा का कार्यक्रम था। दोपहर बाद स्थानीय कार्यकर्ताओं की टोली, श्रद्धेय दत्तोपंत जी से मिलने आई। कार्यकर्ताओं ने बताया कि सायं को सार्वजनिक सभा का कार्यक्रम है।

दत्तोपंत जी ने प्रत्येक कार्यकर्ता का विस्तृत परिचय लिया, सभी को अपने निकट बैठाया, फिर सामान्य जानकारी ली, कि सभा में कितने लोग रहेंगे। किस आयु वर्ग के, किस व्यवसाय वर्ग के लोग रहेंगे और कौन–कौन बोलने वाले है इत्यादि – इत्यादि। फिर पूछा कार्यक्रम में किसी को अध्यक्ष रखा है क्या? कार्यकर्ताओं ने बताया कि " हां, तय किया है।

श्रद्धेय दत्तोपंत जी ने हम सभी को नई–नई जानकरी और कार्यक्रम के बारे में बारीकी से मार्गदर्शन किया।

दत्तोपंत जी ने कहा – जब मंच संचालक अतिथियों को मंच पर आमंत्रित करे, उस समय ध्यान रखें कि कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले, महानुभाव को सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करे। साथ ही कहा कि कार्यक्रम में सर्वाधिक सम्मान करने योग्य होने के कारण, सबसे बीच में, बैठने के लिए अध्यक्ष को ही आग्रह करना चाहिए तथा जब भारत माता के चित्र आदि के समक्ष दीप प्रज्वलन, माल्यार्पण आदि का अनुरोध भी, उद्घोषक, अध्यक्ष को सम्बोधित करते हुए करे।

दत्तोपंत जी ने कहा – जब मंच संचालक अतिथियों को मंच पर आमंत्रित करे, उस समय ध्यान रखें कि कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले, महानुभाव को सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करे। साथ ही कहा कि कार्यक्रम में सर्वाधिक सम्मान करने योग्य होने के कारण, सबसे बीच में, बैठने के लिए अध्यक्ष को ही आग्रह करना चाहिए तथा जब भारत माता के चित्र आदि के समक्ष दीप प्रज्वलन, माल्यार्पण आदि का अनुरोध भी, उद्घोषक, अध्यक्ष को सम्बोधित करते हुए करे।

वक्ताओं का क्रम कैसा रहे, इसका मार्गदर्शन करते हुए दत्तोपंत जी ने कहा वक्ता के नाते जो अपना कार्यकर्ता विषय रखने वाला है, उसे सबसे अन्त में बोलने का कहना चाहिए। मुख्य वक्ता के बाद किसी भी का भाषण नहीं होना चाहिए, उदघोषक को भी कार्यक्रम के अन्त में अधिक बात नहीं करनी चाहिए। आवश्यक सूचना आदि प्रारम्भ में ही दे देनी चाहिए, ताकी लोग कार्यक्रम के बाद अपना विषय घर लेके जाए।

विजयी – विश्वास

मैंने पूछा – आप तो संघ के प्रारंभ से संघकार्य देख रहे है और आज तक देख रहे हैं आपको क्या लगता है? जैसा आप लोगों ने सोचा वैसा ही, संघ चल रहा है? और क्या हम अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे?

श्रद्धेय दत्तोपंत जी ने कहा "इसमें किंचित भी संदेह की आवश्यकता नहीं है। जैसे संघ की हमारी कल्पना थी; योजना थी; ठीक वैसा ही संघ चल रहा है और बन रहा है। फिर कहा कि संघ अपना लक्ष्य निश्चित प्राप्त करेगा। इसका कारण केवल आपका योगदान मात्र नहीं है, यह ईश्वरीय इच्छा है जो सदैव पूरी होती है। ❑

आम आदमी और बजट 2012 पर परिसंवाद

सर्राफा व्यवसाय पर जो टैक्स लगा है यह एक सोची–समझी हुई साजिश है। भारत में प्राचीन काल से आम आदमी अपनी बचत को गहनों जेवरात में निवेश करता था। इसी बचत के चलते भारत वैश्विक मंदी के दौर में भी टिका रहा। अब उस प्रवृत्ति को समाप्त करने की तरफ टेढ़ी दृष्टि कर ली है, सर्राफा व्यवसाय पर लगे इस टैक्स को सरकार को वापस लेना चाहिए।

– डॉ. चंद्रमोहन

स्वदेशी जागरण मंच (बरेली) द्वारा अर्बन कोआपरेटिव बैंक के सभागार में औद्योगिक परिसंवाद से "आम बजट 2012" पर विस्तृत चर्चा हुई।

सर्वप्रथम बाबूगेनू के चित्र पर दीप प्रज्ज्वलन हुआ। तत्पश्चात स्वदेशी जागरण मंच के क्षेत्रीय संयोजक डॉ. चंद्रमोहन ने प्रस्तावना रखी।

उन्होंने कहा कि आम बजट एक सालाना जलसा जैसा ही है। इस बार यह मातमी जलसा आम आदमी को मुँह चिढ़ाता सा दिखा है। इस बजट ने आम आदमी को महंगाई के अलावा सब जगह टैक्स देना पड़ेगा। सरकार आम जनता से छल कर रही है। जनता इस बात को अब समझ रही है, स्वदेशी जागरण मंच इसे आमजन तक पहुंचाएगा।

सर्राफा व्यवसाय पर जो टैक्स लगा है यह एक सोची–समझी हुई साजिश है। भारत में प्राचीन काल से आम आदमी अपनी बचत को गहनों जेवरात में निवेश करता था। इसी बचत के चलते भारत वैश्विक मंदी के दौर में भी टिका रहा। अब उस प्रवृत्ति को समाप्त करने की तरफ टेढ़ी दृष्टि कर ली है, सर्राफा व्यवसाय पर लगे इस टैक्स को सरकार को वापस लेना चाहिए।

आगरा से सी.आई.सी. आई.सी. ए.आई. के पूर्व उपाध्यक्ष उमेश गर्ग विशिष्ट अतिथि के रूप में रहे। उन्होंने कहा त्योहारों का उत्साह बजट के निराशाजनक रूप से पेश होने के कारण फीका हो गया, जब सब चीज महंगी हो रही है तो बजट क्या बना? बजट में अपने संसाधनों का सदुपयोग नहीं किया। वरना महंगाई भी नहीं बढ़ती और देश तरक्की की राह पर चलता।

सी.ए.के.सी. गुप्ता ने कहा बजट में आयकर सीमा 3 लाख रुपए होना था जो मात्र 20,000/– ही बढ़ी, यह भी न बढ़ाते तो क्या होता?

पूर्व केन्द्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने भी कहा कि बजट की तरह नया कोयला घोटाला भी आज का मतदाता देखें कि देश में अर्थव्यवस्था किस तरह चौपट हो रही है।

मुख्य वक्ता स्वदेशी जागरण मंच के पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रांतीय संयोजक आगरा के सी.ए. संजीव माहेश्वरी ने कहा कि बजट की प्रतिक्रिया शेयर मार्केट से आंकी जाती है तो इस बार शेयर मार्केट गिरा। उद्योग जगत ने सरकार पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। इस देश के लोग अपनी आय का 38 प्रतिशत बचत करता है। ऐसे लोगों के देश का बजट आज भीख मांगता जैसा लगता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है।

बजट में प्रत्यक्ष कर के अप्रत्यक्ष करो को बढ़ाया गया और बेहिसाब बढ़ाया जाना चिंताजनक है। बजट ने आमदनी पौने ग्यारह लाख करोड़ जिसमें से राज्यों को देने के बाद 7.71 लाख करोड़ बचा और खर्चा लगभग साढ़े चौदह लाख करोड़, उसमें भी 3 लाख करोड़ प्लान रुपए योजनाओं पर 9 लाख करोड़ नॉन प्लांड खर्चा है और 3.12 लाख करोड़ ब्याज देना है।

सर्राफा व्यवसायी आपसी खरीद में भी एक प्रतिशत टैक्स काटेंगे। इस हिसाब से आम आदमी तक जेवर पहुंचने तक कई गुना टैक्स पड़ जाएगा। 20 लाख की अचल संपत्ति की बिक्री पर भी एक लाख टैक्स जमा करना होगा। यह अप्रत्यक्ष रूप से उगाही हो रही है। सभी सेवाओं पर आम आदमी को 12 प्रतिशत टैक्स देना होगा। पहले यह मात्र 100 सेवाओं पर लगता था वह भी 10 प्रतिशत मात्र अब बस टैक्स ही टैक्स देते जाओ।

कार्यक्रम की अध्यक्षता घनश्याम खण्डेलवाल जी की। उन्होंने कहा कि घोटाले हो रहे हैं तो घाटे का बजट तो आएगा ही। एक बजट से भी ज्यादा की धनराशि एक घोटाले में प्रयुक्त हो रही है। कार्यक्रम का संयोजन प्रांत कोष प्रमुख मनीष अग्रवाल जी ने किया। धन्यवाद महानगर संयोजक आलोक प्रकाश ने प्रेरित किया। कार्यक्रम में एस.पी.एस. चौहान, युवा इकाई के अध्यक्ष अंकित अरोरा, अंशुल गहरोत्रा, प्रियांशु अग्रवाल, संजीव अग्रवाल, डॉ. अनिल गर्ग आदि उपस्थित रहे।

प्रस्तुति : आलोक प्रकाश

खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश – वापस लिया जाए

एक ओर जहां इस देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। वही सरकार के इस निर्णय से दूसरी ओर खुदरा व्यापार में लगे देश के पांच करोड़ कारोबारी बेरोजगार हो जाएंगे। जिसके कारण देश के 26 करोड़ लोगों के सामने रोजी–रोटी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी।
– बन्देशंकर सिंह

दिनांक 7 अप्रैल के दिन स्वदेशी जागरण मंच जमशेदपुर के तत्वाधान में केन्द्र सरकार के द्वारा लिये गये निर्णय खुदरा व्यापार के सिंग्लब्रांड में शत प्रतिशत विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति प्रदान किये जाने और मल्टी ब्रांड में विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान करने के संभावनाओं के खिलाफ एक दिवसीय धरना का आयोजन उपायुक्त कार्यलय जमशेदपुर के सामने किया गया।

इस धरना को विभिन्न समाजिक और व्यापारिक संगठनों का भी सहयोग मिला जिसमें प्रमुख रूप से भारतीय मजदूर संघ, सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जमशेदपुर चैम्बर, खुदरा आलू–प्याज विक्रेता संघ, स्वदेशी विकास परिषद्, कला भारती इत्यादि संगठनों का सहयोग था।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वदेशी जागरण मंच के क्षेत्रीय विचार मंडल प्रमुख बन्देशंकर सिंह ने कहा कि केन्द्र सरकार का यह निर्णय देश को विदेशीयों के हाथों में गिरवी रखने का कार्य करेगी। एक ओर जहां इस देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। वही सरकार के इस निर्णय से दूसरी ओर खुदरा व्यापार में लगे देश के पांच करोड़ कारोबारी बेरोजगार हो जाएंगे। जिसके कारण देश के 26 करोड़ लोगों के सामने रोजी–रोटी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। सरकार उनकी रोजी रोटी छिनने का प्रयास कर रही है जो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने निर्णय को वापस लेने चाहिए।

मंच के जिला संयोजक जे. के. एम राजू ने कहा की अमरीका के दबाव में आकर केन्द्र की यूपीए सरकार ने यह निर्णय लिया है जो अत्यंत ही निंदनीय है।

जिला प्रचार प्रमुख राकेश पाण्डेय ने कहा की सरकार की इस निर्णय से देश के खुदरा व्यापार पर विदेशी बड़ी कंपानियों वॉलमार्ट, टेस्को, कैरीफर इत्यादि का कब्जा हो जाएगा। इन कंपनियों का इतिहास है कि जहां भी ये कंपनियां गई है वहां के खुदरा कारोबार को व्यापार से बाहर कर 80 प्रतिशत बाजार पर कब्जा जमा लिया है। अमरीका और यूरोप के कई देशों में इन कंपनियों के चलते करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं।

इन कंपनियों के इतिहास को देखने के बावजूद भी केन्द्र सरकार क्यूं इनके ऊपर मेहरबान है यह समझने की बात है। धरना कार्यक्रम को स्वदेशी जागरण मंच के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं सहित धरना को सहयोग दे रहे है विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने भी संबंधित किया। इस कार्यक्रम का संचालन मंच के जिला सहसंयोजक डॉ. अनिल राय और धन्यवाद ज्ञापन इस कार्यक्रम के संयोजक राजकुमार साह ने किया। धरना कार्यक्रम में प्रमुख रूप से आनंद मजुमदार, सी. पी. सिंह, शालीग्राम मिस्त्री, कौशल किशोर, रामेश्वर प्रसाद, आर.सी. पाठक, पंकज सिंह, अभिषेक बजाज, अमित, गौरव शंकर, गुरजीत सिंह, मिथलेश प्रसाद, शंकर जोशी, अनिल तिवारी, अरविन्द्र तिवारी, मोहम्मद अमन, राजपती देवी, मंजु, जयंत श्रीवास्तव, देव कुमार, धर्मेन्द्र कुमार, सुजय कुमार, पंकज शाही, संयज मिश्रा, संजीत प्रमाणिक, ललित, एस.एन.राजु, रौशन सिंह और अनेक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। ❑

गो–हत्या प्रतिबंध में कोताही बर्दाश्त नहीं : सत्यानंद झा

जैविक खाद के उपयोग की अपील

चिलगड्डा में गो–विज्ञान केन्द्र का शिलान्यास

बोकारो, झारखंड सरकार के कृषि मंत्री सत्यानंद झा 'बादुल' ने जिले के जरीडीह प्रखंड अंतर्गत चिलगड्डा ग्राम में गो–विज्ञान केन्द्र का शिलान्यास किया। इस अवसर पर अपने सम्बोधन में मंत्री ने मानव जीवन में गाय की महत्ता पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में गाय का स्थान 'मां' से कम नहीं है। उससे प्राप्त होने वाला हरेक चीज काफी उपयोगी, लाभप्रद और अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि गो–हत्या पर प्रतिबंध सख्ती से लागू करने का निर्देश पूरे राज्य में सभी उपायुक्त व पुलिस अधीक्षकों को दिया गया है। नियमावली तैयार नहीं होने के कारण इसका अनुपालन नहीं हो पा रहा था।

वर्ष 2005 में ही लगाये गये गो–हत्या प्रतिबंध को कैबिनेट द्वारा सख्ती से 21 नियमों के तहत दंड का प्रावधान तैयार किया गया है। अब गो–हत्या प्रतिबंध में कोताही बरतने वाले को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जायेगा।

उन्होंने देसी चीजों की अहमियत बताते हुए देशी गायों के संरक्षण व संवर्द्धन की आवश्यकता बतायी। साथ ही किसानों से जैविक खादों का अधिकाधिक उपयोग करने की अपील की।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के कृषि और गव्य विकास विभागों की ओर से जैविक खाद के उत्पादन में किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान देने का प्रस्ताव आगामी बजट में लाया जायेगा।

साथ ही चिलगड्डा गांव के सबसे बड़े तालाब के सौंदर्यीकरण की घोषणा के साथ–साथ त्वरित कार्रवाई करते हुए मत्स्य विभाग को इसे क्रियान्वित करने की दिशा में निर्देश भी दिये।

उन्होंने एक एकड़ से अधिक जमीन वाले किसानों को वह 25 हजार रुपये की लागत वाले कुंए उपलब्ध कराने का भी आश्वासन दिया।

चिलगड्डा में बनने वाले गो–विज्ञान केन्द्र के विकास की सम्पूर्ण जिम्मेवारी लेते हुए श्री बादुल ने कृषि के क्षेत्र में सर्वांगीण विकास का भरोसा दिलाया। साथ ही डोमा नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेक डैम बनाने की भी घोषणा की। यह निर्माण पानी पंचायत के माध्यम से होगा।

समारोह का संचालन स्वदेशी जागरण के राष्ट्रीय परिषद् सदस्य कौशल किशोर तथा धन्यवाद ज्ञापन गो–विज्ञान परीक्षा समिति के जिला नियंत्रक महेन्द्र कुमार सिंह ने किया। मौके पर मंच के प्रांतीय संयोजक सचीन्द्र कुमार बरियार, क्षेत्रीय विचार मंडल प्रमुख बंदेशंकर सिंह, जरीडीह प्रखंड संयोजक पद्मलोचन महतो, अभाविप के सहमंत्री विनोद कुमार, भाजपा जिलाध्यक्ष रोहितलाल सिंह, शशिभूषण ओझा 'मुकुल' आदि मौजूद थे। ❑

:: सफल परीक्षार्थी हुए पुरस्कृत ::

चिलगड्डा में आयोजित समारोह के दौरान राज्य सरकार के कृषि मंत्री सत्यानंद झा 'बादुल' ने बीते 14 अक्तूबर, 2011 को आयोजित गो–विज्ञान परीक्षा के सफल परीक्षार्थियों को पुरस्कृत किया। उन्होंने विभिन्न केन्द्रों में प्रथम, द्वितीय व तृतीय रहे परीक्षार्थियों को प्रशस्ति–पत्र व मेडल देकर पुरस्कृत किया। उक्त परीक्षा चास मंडल उपकारा सहित कुल 37 केन्द्रों पर आयोजित की गयी थी।

:: दो एकड़ भूमि पर बनेगा केन्द्र ::

बोकारो जिले के जरीडीह प्रखंड अंतर्गत चिलगड्डा में दो एकड़ भूमि पर गो–विज्ञान केन्द्र का निर्माण किया जाएगा। यह भूमि वहां के निवासी रूपलाल महतो ने केन्द्र के निर्माण हेतु दान दी है। उक्त केन्द्र में प्राकृतिक तरीके से देसी गायों के संरक्षण व संवर्द्धन के हर संभव उपाय किये जाएंगे।